जनता के गोठ

Website- https://www.jantakegoth.com

● वर्ष -01 ● अंक- 319 ● रायपुर, शुक्रवार 13 नवम्बर 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ- 12 ● मूल्य- 2 रुपया ● संपादक- शुभम वर्मा ● PRGI Reg No : CTBIL/25/A1787

संक्षिप्त समाचार

सीएम योगी 1,146 कनिष्ठ सहायकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके साथ ही अन्नदाताओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 लाभार्थी परिवारों को 215 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण भी किया जाएगा। इसके पहले, सीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने इस कार्य-संस्कृति को बदला है। आज सरकारी नौकरी में सिफारिश नहीं, योग्यता का सम्मान होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नव-चयनित युवाओं को अग्रिम बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, युवाओं की प्रतिभा को सम्मान और संकट की घड़ी में अन्नदाता के परिवार को संबल प्रदान करना डबल इंजन सरकार का संकल्प है।

गुलमर्ग और मनाली में हुई ताजा बर्फबारी, पर्यटकों और पर्यटन से जुड़े लोगों में खुशी की लहर

जम्मू कश्मीर। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थलों गुलमर्ग और मनाली के आसपास हुई ताजा बर्फबारी ने इस पूरे इलाके को एक बेहद खूबसूरत विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है। आसपास के पहाड़ सफेद बर्फ की सुंदर चादर से ढके हुए हैं, जिससे यहां के नजारे बेहद मनमोहक हो गए हैं। गुलमर्ग के कोंगडूरी और अफरवट में ताजा बर्फबारी हुई है। इस ताजा बर्फबारी ने यहां आने वाले पर्यटकों के बीच काफी उत्साह और खुशी भर दी है। साथ ही, स्थानीय निवासियों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में भी इसे लेकर काफी खुशी देखी जा रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी ने गुलमर्ग में पर्यटन गतिविधियों के फिर से जोर पकड़ने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इसे पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों में नई उम्मीदें जगी हैं।

पूर्व पुलिस आयुक्त ने प्रियांक खड़गे को लिखा पत्र, आरएसएस पर बयान को बताया गैर-जिम्मेदाराना

बेंगलुरु। बेंगलुरु के सेवानिवृत्त पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रियांक खड़गे को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे गृह विभाग की प्रतिष्ठा को कम न करें। साथ ही विभाग और कर्नाटक पुलिस की गरिमा, मर्यादा व संस्थागत अखंडता को बनाए रखें। भास्कर राव ने संघ को निशाना बनाते हुए प्रियांक खड़गे के हालिया बयानों, विशेष रूप से नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्याओं के संबंध में टिप्पणियों पर चिंता जताई।

किसानों को बड़ी राहत

कम धान उपजने पर भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ का मिलेगा लाभ

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी के बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार धान खरीदी की व्यवस्था में ऐसा बदलाव करने की तैयारी में है, जिससे कम उत्पादन होने पर भी किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा के अनुसार किसानों को पूरी आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था कर सकती है। इस संबंध में 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस व्यवस्था की अंतिम शर्तों और भुगतान के तरीके को लेकर सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम की अनिश्चितता, सिंचाई की सीमित सुविधा और अन्य कारणों से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं मिल पाता। ऐसे में निर्धारित खरीदी सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसान अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने को मजबूर हो जाते थे। इससे बिचौलियों को भी फायदा पहुंचता था। नई व्यवस्था लागू होने पर किसानों को अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिलेगी और निर्धारित सीमा के शेष हिस्से पर भी आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुल सकता है। धान खरीदी में फर्जी रकबे, दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने और उपार्जित धान की दोबारा बिक्री जैसी शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। सरकार ने इस पर



नियंत्रण के लिए पंजीयन, रकबा सत्यापन और खरीदी केंद्रों की निगरानी को सख्त किया है। सरकार की मंशा है कि खरीदी केंद्रों तक केवल वास्तविक किसानों की उपज पहुंचे। यदि कम उत्पादन वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा के अनुरूप आर्थिक सहायता मिलती है, तो अतिरिक्त धान जुटाने के लिए बिचौलियों पर उनकी निर्भरता घटेगी। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में करीब 149 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ था। वहीं, वर्ष 2025-26 में खरीदी घटकर लगभग 141 लाख मीट्रिक टन रह गई। नई व्यवस्था और सख्त निगरानी के चलते चालू सीजन में वास्तविक धान खरीदी करीब 125 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि की व्यवस्था को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन और खेती की परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक सहायता देना है। सरकार का जोर किसानों को धान के अलावा दलहन, तिलहन और दूसरी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करने पर है।

धान के समर्थन मूल्य में की 72 रुपये की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने खरीफसीजन 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता जोड़कर किसानों को धान के लिए कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रही है। धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस बार डिजिटल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन मान्य किए जाने से उन्हें दोबारा पंजीयन की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए धान के वास्तविक रकबे का सत्यापन किया जा रहा है।

कबराकान हाथी का खूनी तांडव जारी

एक और महिला को उतारा मौत के घाट..

सूरजपुर। सूरजपुर वन मण्डल के रामानुजनगर वन परिक्षेत्र स्थित महंगई व कटेलपारा के जंगल में मौजूद कबराकान हाथी का खूनी तांडव जारी है. बीती रात उसने रामानुजनगर वन परिक्षेत्र के उमेश्वरपुर में एक और महिला को उतारा मौत की घाट उतार दिया. कबराकान हाथी ने 45 वर्षीय दिलासो पति अर्जुन को हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. कबराकान हाथी के लगातार आतंक से वन विभाग की निगरानी और मॉनिटरिंग व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. बीते एक एक सप्ताह के दौरान हाथी के



हमले से 5 लोगों की जान जा चुकी है. लगातार हो रहे हमलों और जान रही मासूम ग्रामीणों की जान से क्षेत्र के लोगों में दहशत और आक्रोश देखने को मिल रहा है. इसके पहले वन विभाग ने रातों में भी जंगलों में मानिटरिंग करने का ढिंढोरा पीटा था।



राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक धनंजय मुंडे ने महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की।

चार दिन चलेगी सदन की कार्यवाही

14 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का 17वां सत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के 17वें सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विधानसभा का आगामी सत्र 14 दिसंबर 2026, सोमवार से शुरू होकर 17 दिसंबर 2026, गुरुवार तक चलेगा। इस दौरान सदन की कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक, चार दिवसीय इस सत्र में वित्तीय कार्यों के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। इस दौरान सरकार के वित्तीय कामकाज और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय



सदन के सामने रखे जाएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष जहां सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और विभागीय कामकाज से जुड़े विषयों को सदन में रखेगा, वहीं विपक्ष को भी सरकार से सवाल पूछने और विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगने का अवसर मिलेगा।

बीजेपी मुख्यालय में दिवाली मिलन समारोह

पीएम बोले-2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य नामुमकिन नहीं

नई दिल्ली/एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के बदलते स्वरूप, अपने राजनीतिक सफर और केंद्र सरकार के 25 वर्षों के अनुभवों को साझा किया। साथ ही पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए विकसित भारत का सपना पूरा करना नामुमकिन नहीं



है। पीएम मोदी ने 90 के दशक की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उन्हें देशभर में दो बड़ी यात्राओं की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने बताया कि उस दौर में प्रेस रिलीज भेजने के लिए भी फैक्स मशीन ढूंढनी पड़ती थी। उन्होंने अपने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। पीएम ने बताया कि एक दिन दिल्ली स्थित 11 अशोक रोड के उनके कमरे में पत्रकारों का समूह पहुंचा और मिठाई खिलाने की मांग की। पत्रकारों ने उन्हें बताया कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बाद में यह खबर सही साबित हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रमुख के रूप में उनके 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान देश, दुनिया और राजनीति करने का तरीका काफी बदल गया है। टेक्नोलॉजी के विकास ने मीडिया का स्वरूप भी पूरी तरह बदल दिया है। पारंपरिक मीडिया के

फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, एक भारतीय नाविक घायल : केंद्रीय मंत्री सोनोवाल

नई दिल्ली। फारस की खाड़ी में लाइबेरिया के झंडे वाले तेल-टैंकर पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक के घायल होने की सूचना है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। सोनोवाल ने एक्स पोस्ट में बताया कि एमची फुजैराह एनर्जी नाम का यह जहाज अल-रुवाइस से दुबई जा रहा था, तभी इस पर किसी वस्तु (प्रोजेक्टाइल) से हमला हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 10 नवंबर को, लाइबेरिया के झंडे वाले वीएलसीसी एमटी फुजैराह एनर्जी शिप जिसमें 6 भारतीय नाविक सवार थे।

सियासी गलियारों में हलचल मचा दी

वह कुशल वक्ता,मेहनती इंसान हैं पित्रोदा ने पीएम मोदी की तारीफ

नई दिल्ली/एजेंसी

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना करते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. सैम पित्रोदा ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक अच्छा वक्ता करार दिया है. पित्रोदा ने पीएम मोदी को एक बेहतरीन वक्ता होने के साथ-साथ अत्यंत मिलनसार, दयालु, स्नेही और दूसरों की परवाह करने वाला व्यक्ति करार दिया है. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर सबको सकते में डाल



दिया है. उनका यह बयान लोगों को चौंका दिया है. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'कुशल वक्ता' और 'मेहनती इंसान' बताया है. पित्रोदा ने कहा कि हमारे बीच कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं हैं. एक गुजराती नेता, मित्र और शुभचिंतक के रूप में, मुझे पीएम मोदी से कोई शिकायत नहीं है. बता दें कि सैम पित्रोदा का यह चौंकाने वाला बयान उस सवाल के जवाब में आई, जिसमें कांग्रेस संसदीय दलकी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा कभी प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा वक्ता बताए जाने का जिक्र था. दरअसल, राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था.राहुल गांधी के खिलाफभाजपा के 'विदेशी हस्तक्षेप' के दावों को पित्रोदा ने 'घिसा-पिटा राजनीतिक हौवा करार दिया था. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ उनका कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है।

ईडी का वारंट आवेदन खारिज

महादेव ऐप केस-सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले के प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सौरभ चंद्राकर को कड़ी सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहीं, पूछताछ के लिए श्वष्ठ की ओर से मांगी गई रिमांड को अदालत ने मंजूरी नहीं दी। मिली जानकारी के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम अपने कार्यालय से लेकर रायपुर की विशेष अदालत पहुंची थी। इससे पहले सीबीआई ने अदालत से मिली 8 दिनों की रिमांड पर उससे पूछताछ की थी। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि,सीबीआई आगे की पूछताछ के लिए एक बार फिर रिमांड की मांग कर सकती है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने भी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के लिए अदालत में रिमांड की मांग रखी थी, लेकिन फिलहाल श्वष्ठ को इसमें सफलता नहीं मिली। अदालत के आदेश के बाद सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। अब इस हाईप्रोफाइल मामले में आगे की जांच और दोनों केंद्रीय एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सीबीआई मुख्यालय में आठ दिनों तक चली पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर से जुड़े कई अहम खुलासों की जानकारी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूछताछ में सौरभ ने महादेव ऐप के कथित लाइजनिंग नेटवर्क से अपनी भूमिका अलग बताई



है। बताया जा रहा है कि, उसने लाइजनिंग का काम रवि उप्पल के जिम्मे होने की बात कही। वहीं, सौरभ ने कथित तौर पर पैनल ऑपरेशन और हवाला के जरिए होने वाले वित्तीय लेन-देन से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी संभालने की बात स्वीकार की है। हालांकि, इन दावों और पूछताछ में सामने आए बयानों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सीबीआई की पूछताछ में शुभम सोनी का कथित वीडियो भी चर्चा का विषय रहा। इस वीडियो में शुभम सोनी ने दावा किया था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल उसके अधीन काम करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई ने इसी वीडियो का हवाला देते हुए सौरभ से सवाल-जवाब किए। बताया जा रहा है कि वीडियो में किए गए दावों को लेकर पूछे गए सवालों पर सौरभ ने शुभम सोनी से ही इस बारे में पूछने की बात कही। उल्लेखनीय है कि, सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के बाद भारत लाया गया था। भारत पहुंचने के बाद सीबीआई ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इसके बाद उसे रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां से जांच एजेंसी को आठ दिनों की पुलिस रिमांड मिली थी। इस दौरान सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के संचालन, कथित सट्टेबाजी नेटवर्क, करोड़ों के वित्तीय लेन-देन, हवाला कनेक्शन और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को लेकर पूछताछ की।

दुबई से रवि उप्पल को ईडी लाएगा भारत, तैयार किया 400 पन्नों का दस्तावेज



महादेव सट्टा एप केस मामले में मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। दुबई में पकड़े गए रवि उप्पल को भारत लाने की तैयारी अब तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने करीब चार सौ पन्नों का विस्तृत डोजियर तैयार किया है। यह दस्तावेज अंग्रेजी और अरबी भाषा की दो अलग फाइलों में बनाए गए हैं। इन सभी कागजातों को केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी को सौंप दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी इस मामले में अपने जरूरी दस्तावेज भेज दिए हैं। इससे रवि उप्पल के भारत आने का रास्ता साफहोता दिख रहा है।

वोट बचाओ – देश बचाओ ' अभियान के तहत दुर्ग (ग्रामीण) जिले में मंडलस्तरीय जनचौपाल एवं संवाद कार्यक्रम की शुरुवात

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ।

दुर्ग - अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 'वोट बचाओ॒देश बचाओ' अभियान के अंतर्गत जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में जिलेभर में मंडलस्तरीय जनचौपाल एवं संवाद कार्यक्रमों का शुरुवात किया गया।

इसी कड़ी में आज जिले के दो मंडलों में जनचौपाल एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडल कांग्रेस कमेटी हथखोज, भिलाई-चरोदा के तत्वावधान में उमदा चौक तथा मंडल कांग्रेस कमेटी चरोदा के तत्वावधान में काली मंदिर रोड, चरोदा के समीप जनचौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, महापौर निर्मल कोसरे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का मताधिकार है। यदि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं, तो यह केवल किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। आज देशभर में मतदाता सूची, चुनावी पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी इन सवालों को जनता के बीच ले जाकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जनजागरण कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता और पारदर्शिता के बजाय सत्तारूढ़ भाजपा के प्रति पक्षपात दिखाई दे रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और भाजपा के बीच सांठगांठ को लेकर जो सवाल विपक्ष और आम जनता उठा रहे हैं, उनका जवाब देश की जनता के सामने आना चाहिए। निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक



संस्था किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव से मुक्त होकर कार्य करे, यही लोकतंत्र की बुनियादी अपेक्षा है। राकेश ठाकुर ने कहा कि जब चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर ही प्रश्न उठने लगें, तब उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है। कांग्रेस की मांग है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, मतदाताओं के नाम काटे जाने और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो, चुनावी अनियमितताओं से जुड़े सवालों का सार्वजनिक जवाब दिया जाए तथा निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बिना किसी राजनीतिक दबाव के करे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठ रहे गंभीर सवालों के मद्देनजर कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर लगातार चिंताएं सामने आ रही हैं। लोकतंत्र केवल पांच साल में एक बार मतदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मतदाता का विश्वास, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं और विपक्ष की आवाज का सम्मान भी शामिल है। यदि जनता के वोट की ताकत को कमजोर करने का प्रयास होता है, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 11 से 15 नवंबर 2026 तक जिले के सभी 39 मंडल कांग्रेस कमेटियों के तत्वावधान में अलग-अलग स्थानों पर मंडलस्तरीय जनचौपाल एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में आम नागरिकों, युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं एवं विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। मताधिकार की सुरक्षा, मतदाता सूची की पारदर्शिता, निर्वाचन आयोग की जवाबदेही, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडलस्तरीय कार्यक्रमों के सफल आयोजन के पश्चात अभियान को बूथ स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। प्रत्येक बूथ पर जनचौपाल एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित कर आम मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता गांव, मोहल्ले, पंचायत और बूथ तक पहुंचकर लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। जनता की समस्याओं, सुझावों और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों को भी सुना जाएगा, ताकि इस अभियान को केवल राजनीतिक कार्यक्रम न बनाकर व्यापक जनभागीदारी का आंदोलन बनाया जा सके।

मावलीगुड़ा में कांग्रेस ने लगाई जन चौपाल, मतदाता अधिकारों की रक्षा का लिया संकल्प

वोट बचाओ॒देश बचाओ अभियान के तहत ग्रामीणों से लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हुई चर्चा



ओमप्रकाश रजक /जनता के गोठ जगदलपुर। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार नानगुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तुसेल मंडल अंतर्गत मावलीगुड़ा पंचायत में वोट बचाओ॒देश बचाओ अभियान के तहत जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ लोकतंत्र की मजबूती और मतदाता अधिकारों को लेकर चर्चा की।

जन चौपाल में मतदाता सूची में पारदर्शिता, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया तथा प्रत्येक नागरिक के मतदान के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है। मतदाता सूची में पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वोट की रक्षा से ही लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित होगी। पार्टी का संकल्प है कि जनता के मताधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य, महामंत्री अभिषेक नायडू, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल, नानगुर ब्लॉक प्रभारी विजय सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष फूलसिंह बघेल, जिला सचिव हीरालाल ध्रुव, जनपद सदस्य अनीता पोयम सहित सुरेंद्र त्रिपाठी, सदाशिव, गंगा सेठिया, श्यामलाल सोनी, संजय सोनी, मंगलू, देवनाथ, धनीराम नेताम, सामनाथ मौर्य, भारतुनाथ नाग, हरेन्द्र सोनी, पुरुषोत्तम सोनी, महाराव पोयम, त्रिनाथ यादव, चमरा बघेल, पांचों बघेल, पांचों कश्यप, चितु नाग, लाचू बघेल सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास अधीक्षकों की प्रदेशव्यापी हड़ताल

मांगों के समर्थन में सौंपा ज्ञापन, निराकरण नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी



कबीरधाम। छात्रावास एवं आश्रम अधीक्षकों की पांच सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर गुरुवार 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय सामूहिक सांकेतिक हड़ताल की गई। इस दौरान अधीक्षकों ने एकजुट होकर शासन-प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित कराया।

संघ की प्रमुख मांगों में अधीक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों एवं कार्य अवधि का निर्धारण, कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति की व्यवस्था, ड्डस्थ ऐप से उपस्थिति संबंधी समस्या का निराकरण, ऑनलाइन उपस्थिति एवं अवकाश व्यवस्था में सुधार तथा छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त बजट और सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक विद्यार्थियों की सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें 24 घंटे छात्रावास परिसर में उपस्थित रहने जैसी व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधीक्षकों ने निर्धारित कार्य अवधि, अवकाश और ड्यूटी व्यवस्था स्पष्ट करने की मांग की है। साथ ही छात्रावासों में दैनिक उपयोग की सामग्री, चिकित्सा, रसोई और राशन के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई।

प्रदेशव्यापी आंदोलन में कबीरधाम जिला इकाई ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। अधीक्षकों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के नाम अतिरिक्त कलेक्टर नरेंद्र पैंकरा को ज्ञापन सौंपा।

संघ ने कहा कि ये मांगें केवल अधीक्षकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने से भी जुड़ी हैं।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शासन-प्रशासन द्वारा मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

कर्मचारियों का हक देने में देरी, अब सम्मान समारोह से वाहवाही लूट रहे महापौर : राजेश चौधरी

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्षों तक भुगतान के लिए भटकाया, कांग्रेस पार्षद दल के दबाव के बाद आयोजित किया जा रहा सम्मान समारोह



ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ

जगदलपुर। नगर पालिक निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान समारोह को लेकर महापौर संजय पांडे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को शाल-श्रीफल देकर सम्मानित करना अच्छी परंपरा है, लेकिन वर्षों तक उनकी मेहनत की कमाई और सेवानिवृत्ति की देय राशि रोककर रखना महापौर की नाकामी का प्रमाण है। राजेश चौधरी ने आरोप लगाया कि निगम के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन सम्मानजनक विदाई तो दी गई, लेकिन जीपीएफ, सीपीएफ परिवार कल्याण निधि सहित अन्य स्वत्वों की पूरी राशि समय पर नहीं मिल पाई। कर्मचारियों को अपनी ही जमा पूंजी के लिए महीनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े और उनकी आर्थिक योजनाएं प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद दल ने निगम की बैठकों में लगातार कर्मचारियों के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया और राशि जारी करने के लिए दबाव बनाया। अब टाउन हॉल में भव्य आयोजन कर महापौर अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं। कर्मचारियों का भुगतान करना निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है, किसी जनप्रतिनिधि का एहसान नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संबंधी देय राशि लगभग तीन वर्षों तक लंबित क्यों रही और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन्होंने निगम आयुक्त की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग और आयोजनों पर जवाबदेही तय करने की मांग की। राजेश चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों का वास्तविक सम्मान फूल-माला और शाल-श्रीफल से नहीं, बल्कि उनके अधिकारों का समय पर भुगतान करने से होता है। महापौर को फोटो सेशन और प्रचार की राजनीति छोड़कर कर्मचारियों के हितों तथा शहर की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, मधोता सेक्टर के 12 मतदान केंद्रों में चस्पा की गई सूची

बीएलओ ने संभाली जिम्मेदारी, मतदाताओं से नाम और विवरणों का सत्यापन करने की अपील

भुजबल बघेल

बकावंड जनता के गोठ बस्तर* विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 85 में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके तहत संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची चस्पा कर आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई। मधोता सेक्टर के अंतर्गत भाग संख्या 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 101 एवं 109 सहित कुल 12 मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत



मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के साथ ही नाम जोड़ने, विलोपन एवं विवरणों में संशोधन कराने का अवसर मिलेगा। इस कार्य में बीएलओ लक्ष्मीनारायण ठाकुर, गणेशराम बघेल, राजू बघेल, रामनिवास देहारी, नडगूराम कश्यप, हितेश कुमार पोटाई, टिकमचंद साहू, सुरेश्वर कश्यप, कंशराम बघेल, गोपीनाथ पांडे एवं रमेश टेकाम द्वारा जिम्मेदारी निभाई जा रही है। वहीं सेक्टर सुपरवाइजर कृष्णा सिंह ठाकुर सभी मतदान केंद्रों में पुनरीक्षण कार्य की निगरानी करते हुए बीएलओ को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।

मतदाता सूची में नाम जांचना जरूरी- निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने संबंधित मतदान केंद्र पहुंचकर प्रकाशित सूची में अपना नाम, आयु, पता एवं अन्य विवरणों की जांच अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो अथवा पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं हो, तो निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित बीएलओ के पास आवेदन प्रस्तुत करें। समय रहते सूची का सत्यापन करने से निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी।

पंचायत परिसर में सरपंच से मारपीट का आरोप, सरपंच, पंच समेत दर्जनों ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय, सख्त कारवाई की कर रहे मंगा

कवर्धा: कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत भागुटोला में कचरा फेंकने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। पंचायत परिसर में कचरा फेंकने का विरोध करना सरपंच को भारी पड़ गया। सरपंच चिंताराम साहू ने गांव के ही कुछ लोगों पर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना के वक्त पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद थे। मामले में सरपंच की शिकायत पर कवर्धा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 115(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सरपंच ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

दरअसल, पूरा मामला ग्राम पंचायत भागुटोला का है। सरपंच चिंताराम साहू के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 की सुबह करीब 7:30 बजे जब वे पंचायत भवन पहुंचे और परिसर का ताला खोला, तो वहां चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ मिला। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने अपने घरों का कचरा



पंचायत परिसर में फेंक दिया था। सरपंच का कहना है कि उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में संबंधित लोगों को समझाइश देने की कोशिश की। लेकिन इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि नोकचंद साहू और अन्य लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। सरपंच ने अपने आवेदन में यह भी बताया है कि पंचायत परिसर में निजी सामान रखने और कांच के टुकड़े जैसी नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं फेंकने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद इस तरह की गतिविधियां जारी रहने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास अधीक्षक संघ की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, जिलेभर के अधीक्षक हुए एकजुट

नीलकंठ धिरहे

सक्ती। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के आह्वान पर गुरुवार 12 नवंबर को जिलेभर के छात्रावास अधीक्षकों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। अधीक्षक संवर्ग की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर संघ के सदस्यों ने एकजुट होकर शासन का ध्यान आकर्षित किया।

संघ की प्रमुख मांगों में अधीक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों का निर्धारण शामिल है। इसके तहत कार्य के घंटे, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश का प्रावधान तथा ड्यूटी रोस्टर व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। साथ ही महिला अधीक्षकों के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी करने और अधीक्षक आवास की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने की मांग उठाई गई।

दूसरी मांग में कैडर पुनर्गठन कर मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं अन्य उपयुक्त विभागीय पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की गई है।



तीसरी मांग के तहत शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को ड्डस्थ ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि इससे शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षक विद्यालयीन एवं छात्रावास संबंधी दोनों जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे।

चौथी मांग ऑनलाइन उपस्थिति एवं ॥रू व्यवस्था में सुधार और मेस राशि में अनुचित कटौती पर रोक लगाने से संबंधित है। संघ ने मांग की है कि 30 दिन मेडिकल अवकाश का प्रावधान ॥रू में भी लागू किया जाए, आवश्यक संसाधन कंप्यूटर, इंटरनेट एवं ऑपरेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही दो-तीन दिन की अनुपस्थिति पर मेस राशि में कटौती नहीं हो तथा न्यूनतम 24 दिन की उपस्थिति पर पूर्ण मेस बजट स्वीकृत किया जाए। तकनीकी समस्याओं के कारण अधीक्षकों को जिम्मेदार नहीं ठहराने की भी मांग की गई है। पांचवीं मांग छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त बजट एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। इसमें दैनिक सामग्री, दवाइयां, आयोजन, परिवहन एवं आकस्मिक व्यय के लिए पर्याप्त राशि समय पर जारी करने, शासकीय कार्यों के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता प्रदान करने तथा स्वीकृत राशि समय पर उपलब्ध कराने की मांग शामिल है, ताकि अधीक्षकों को निजी धन खर्च करने की मजबूरी न हो। संघ ने स्पष्ट किया है कि छात्रावासों के बेहतर संचालन और अधीक्षक संवर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए इन मांगों पर शासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है।

जनजातीय समाज भारत की आत्मा है तो उसके जल, जंगल और जमीन की रक्षा कौन करेगा? भाजपा सरकार पहले इसका जवाब दे : रिंकी पाण्डेय

रायगढ़। राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह के बयान कि ÷जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, भारत की आत्मा है÷ पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रिंकी पाण्डेय ने कहा कि जनजातीय समाज को भारत की आत्मा बताना अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा सरकार वास्तव में जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा कर रही है?

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज केवल चुनाव के समय याद आने वाला समुदाय नहीं है। वह छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, प्रकृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा है। भगवान बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे जननायकों का नाम लेने से आदिवासी समाज के प्रति जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। उनके विचारों और संघर्षों को जमीन पर उतारना भी जरूरी है।

रिंकी पाण्डेय ने कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल जल, जंगल और जमीन का है। एक ओर भाजपा सरकार जनजातीय समाज को भारत की आत्मा बताती है, वहीं दूसरी ओर जंगलों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं हैं, बल्कि आदिवासी समाज की आजीविका, संस्कृति, परंपरा और जीवन का आधार हैं। जब जंगलों पर संकट आएगा तो आदिवासी समाज के अस्तित्व पर भी संकट आएगा।

उन्होंने सवाल किया कि आखिर जंगलों की कटाई पर सरकार की जवाबदेही क्या है? वन



अधिकार कानून के तहत कितने पात्र आदिवासी परिवारों को वास्तविक अधिकार मिले हैं? पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन कितना हुआ है? आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति क्या है? इन सवालों का जवाब भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों और जमीनी काम से देना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि जनजातीय समाज को केवल गौरव दिवस मनाने और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्हें उनकी जमीन पर अधिकार, जंगलों की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, बच्चों को बेहतर शिक्षा और महिलाओं को सुरक्षा एवं सम्मान चाहिए।

कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आदिवासी समाज किसी राजनीतिक दल का वोट बैंक नहीं, बल्कि देश की अमूल्य विरासत है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और आदिवासी हितों की रक्षा की आवाज उठाई है। वन अधिकार कानून और पेसा कानून जैसे प्रावधान इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहे हैं।

रिंकी पाण्डेय ने भाजपा सरकार से सवाल किया कि यदि जनजातीय समाज वास्तव में भारत की आत्मा है, तो उसके जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों नहीं है?

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को मंचों से सम्मानित करने से ज्यादा जरूरी है कि उसके अधिकारों की रक्षा की जाए। याद रखिए, जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी आदिवासी संस्कृति सुरक्षित रहेगी और आदिवासी संस्कृति सुरक्षित रहेगी तभी छत्तीसगढ़ की असली पहचान सुरक्षित रहेगी।

सिर्फ आदिवासी समाज को भारत की आत्मा कहने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, उस आत्मा के अस्तित्व की रक्षा करके दिखाना पड़ता है।

डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में घायलों को मिल रहा बेहतर उपचार, डॉक्टरों और नर्सों की सेवा सराहनीय

बस्तर से ओडिशा तक के सड़क दुर्घटना पीड़ित पहुंच रहे अस्पताल, स्वस्थ होकर लौट रहे मरीज

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ जगदलपुर। बस्तर संभाग के जगदलपुर स्थित डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की टीम दिन-रात मरीजों के उपचार और देखभाल में जुटी हुई है। विशेष रूप से सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।

डिमरापाल मेडिकल कॉलेज



अस्पताल में लगभग 20 वर्ष के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक विभिन्न आयु वर्ग के दुर्घटना पीड़ित उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। बस्तर जिले के अलावा संभाग के अन्य क्षेत्रों और पड़ोसी राज्य ओडिशा से भी बड़ी संख्या में घायल मरीज यहां इलाज कराने आ रहे हैं। इससे अस्पताल की क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है।

अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा मरीजों की स्थिति के अनुसार उपचार किया जा रहा है। वहीं नर्सिंग स्टाफ भी मरीजों की नियमित देखभाल और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की निरंतर सक्रियता और बेहतर देखभाल से कई मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की चिकित्सा टीम की सक्रियता मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत का माध्यम बन रही है। डॉक्टरों और नर्सों की समर्पित सेवा तथा उपचार में उनकी भूमिका सराहनीय है।

ठेका मजदूरों ने मांगों को लेकर किया आन्दोलनः 7 घण्टे बंद रही रानी अटारी खदान, प्रबंधन ने दिया लिखित आश्वासन

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल की रानी अटारी खदान में ठेका मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार आंदोलन किया। छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों ठेका श्रमिकों ने मंगलवार सुबह 6 बजे से खदान बंद कर कोयला परिवहन रोक दिया। करीब 7 घंटे तक चले इस आंदोलन के कारण खदान में उत्पादन पूरी तरह ठप रहा। आंदोलन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।

यह मामला एसईसीएल के चिरमिरी क्षेत्र अंतर्गत रानी अटारी और विजय वेस्ट भूमिगत खदानों में कार्यरत ठेका मजदूरों से जुड़ा है। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें पेमेंट स्लिप, पहचान पत्र (आई कार्ड), सुरक्षा उपकरण और एचपीसी (हाई पावर कमेटी) की निर्धारित दरों के अनुसार मजदूरी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा समय पर वेतन भुगतान, पीएफ की जानकारी और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। सात घंटे तक खदान बंद रहने के बाद एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र के महाप्रबंधक ने मजदूरों की मांगों को जायज मानते हुए उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद किसान सभा के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन समाप्त किया गया।

आंदोलन को कोयला श्रमिक संघ सीटू ने भी समर्थन दिया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष वीएम मनोहर ने कहा कि ठेका श्रमिकों को पहचान पत्र, पेमेंट स्लिप, पीएफ की जानकारी और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना उनका अधिकार है। ठेकेदार या एसईसीएल प्रबंधन मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत झा ने आरोप लगाया कि कोयला खदानों में ठेका मजदूरों को कम मजदूरी देकर उनका शोषण किया जा रहा है। मजदूरों को पेमेंट स्लिप नहीं दिए जाने के कारण उन्हें यह तक पता नहीं चल पाता कि उन्हें निर्धारित मजदूरी मिल रही है या नहीं और कितने दिनों का वेतन दिया जा रहा है।

'मनभावन कातिक महीना'



कुम्हड़ा-कोचई के साग सिरागे, फूटगे सबो पटाखा। नइ बाँचिस सुरहोती के थोरको, पेड़ा, खील - बताशा।। बाहिर-भीतर म सबो रेंगिस, लटपट ले मिले रिहिस। देखा-देखी म हमू झपायेन, बन गेन हमन तमाशा।।

गूँथे रहेन झालर-लड़ी ल, उनला धरत-सकेलत हन। अड़बड़ होगे जींस-टॉप, अब स्वेटर-कंबल हेरत हन।। राम-रमउवा, राम-भजन, घर लहुटगे समधी- सजन। गोवर्धन ल बने खुंदायेन, माथ चिक्कन धोवत हन।।

दियना जलायेन येती-वोती, वोकरो लगथे जोरा हा। मान- गउन ल पाईस सुग्घर, लहुटिस गौरी- गौरा हा। मनभावन हे कातिक महीना, दिया-बाती अंगना-अंगना।

दिन हावय मातर-मड़ई के, रिगबिग तुलसी चौरा हा।।

रोशन साहू 'मोखला (राजनांदगांव)
7999840942

दुर्ग के चार थाना क्षेत्रों में सात झपटमारी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 3.60 लाख का सामान बरामद

दुर्ग। दुर्ग जिले के चार थाना क्षेत्रों में नेशनल हाईवे और व्यस्त मार्गों पर महिलाओं को निशाना बनाकर मोबाइल, नकदी और आभूषणों की झपटमारी करने वाले आरोपी को खुर्सीपार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल सहित करीब 3 लाख 60 हजार रुपये का सामान बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार, खुर्सीपार थाना क्षेत्र में लगातार हो रही झपटमारी की घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई थी। खुर्सीपार पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ष्टष्ट) ने अन्य संबंधित थानों के साथ मिलकर जांच शुरू की। इस दौरान घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और तकनीकी साक्ष्यों के साथ मुखबिर तंत्र की मदद से संदिग्ध की तलाश की गई। संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान लक्ष्मण राव (29 वर्ष), पिता एस. सीमांचल राव, निवासी डी.एम.सी. तालाब, कुम्हारी, जिला दुर्ग के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने खुर्सीपार थाना क्षेत्र में तुलसी ट्रेडर्स के सामने खुर्सीपार चौक और डबरा पारा ओवरब्रिज पर दो वारदातों को अंजाम दिया था। इसके अलावा पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे, जामुल थाना क्षेत्र के नंदनी रोड, छावनी थाना क्षेत्र के पावर हाउस ओवरब्रिज तथा सुपेला थाना क्षेत्र में चंद्र मौर्य टॉकीज के पास और ओवरब्रिज पर झपटमारी की थी। इन सात घटनाओं में मोबाइल, बैग, नकदी, सोने के आभूषण, बैंक कार्ड और जरूरी दस्तावेज छीने गए थे।

आरोपी के कब्जे से एक होंडा सीबी शाइन मोटरसाइकिल, 5 ग्राम का सोने का सिक्का, टूटा हुआ सोने का मंगलसूत्र, चार मोबाइल फोन, दो बड़े पर्स और बैग तथा 1,300 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के एटीएम और डेबिट कार्ड, दो एसबीआई पासबुक, एक चेकबुक, पहचान पत्र, अन्य दस्तावेज और डायरी भी जब्त की गई है। बरामद मशरूका की कुल कीमत करीब 3.60 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों, ओवरब्रिज और सुनसान रास्तों पर चलते समय मोबाइल, पर्स और आभूषणों का विशेष ध्यान रखें। बैग सड़क की तरफ लटकाकर न चलें और सड़क पर चलते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें। इस तरह की घटना होने या किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, भवन निर्माण रोकने वार्डवासियों ने की शिकायत

जगदलपुर के लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 08 में ऑफिसर कॉलोनी के पीछे श्व2स्त्र कि सरकारी जमीन पर निर्माण का मामला, पुलिस कर्मचारी पर भी लगाए आरोप

जगदलपुर जनता के गोठ । शहर के लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 08 के पम्प हाउस गली स्थित ऑफीसर कॉलोनी के पीछे श्व2स्त्र कि शासकीय भूमि पर भवन निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। इस मामले में वार्डवासियों ने संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर शासकीय भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोकने तथा मामले की जांच कराने की मांग की है।

शिकायत में वार्डवासियों ने आरोप लगाया है कि एक पुलिस



कर्मचारी द्वारा शासकीय भूमि पर भवन निर्माण कराया जा रहा है। शिकायत के अनुसार, उक्त भूमि पर पहले भी निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति जताई गई थी तथा राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। इसके बावजूद दोबारा उसी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किए जाने का आरोप लगाया गया है।

कलेक्टर,निगम आयुक्त, तहसीलदार,मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक निर्माण विभाग जगदलपुर,अधीक्षक, को दिनांक 4/11/2026 को लिखित आवेदन देने के पश्चात भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है श्व2स्त्र कि शासकीय भूमि पर 2 वर्ष पूर्व निर्माण कार्य को तोड़कर प्लाट खाली करवाया गया था किंतु पुनः उक्त भूमि पर इसी व्यक्ति के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है और ढलाई लेवल पर निर्माण कार्य पहुंच गया है तत्काल जिम्मेदार इस पर रोक लगाये

चर्च में घुसकर हंगामाः महिलाओं से विवाद और युवक से मारपीट का आरोप, मसीही समुदाय ने किया चक्काजाम

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविवार दोपहर चर्च में हंगामे के बाद तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों पर चर्च में घुसकर महिलाओं से विवाद करने और एक युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना से नाराज मसीही समुदाय के लोगों ने कोरबा-रजगामार मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। मामला रजगामार चैकी क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर कुछ लोग चर्च के अंदर पहुंच गए और वहां मौजूद महिलाओं से विवाद करने लगे। इस दौरान विरोध करने पर एक युवक के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। घटना की खबर फैलते ही मसीही समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए।

वहीं, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की गतिविधियों का विरोध किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मामला सामने आ रहा है। धर्म परिवर्तन के आरोप और चर्च में हुए विवाद के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया।

घटना से नाराज मसीही समुदाय के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोरबा-रजगामार मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक जाम रहने के कारण मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी और शिकायत के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया। एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी रजगामार क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान भी पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की थी। इसके बावजूद एक बार फिर इसी तरह का विवाद सामने आने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है।

कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोगों को समझाइश देकर चक्काजाम समाप्त करा दिया गया है।

कैंसर की सस्ती दवाएं : नए सीमित मार्जिन का मरीजों पर क्या होगा असर

कोरिया। भारत सरकार की प्राथमिकता हर परिवार को किफायती और गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार उपलब्ध कराना है। 17 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30त्न तक सीमित कर दिया। संशोधित मूल्य 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी हो गए। 9 नवंबर, 2026 तक, 85 कंपनियों ने 121 दवाओं के लिए संशोधित एमआरपी की घोषणा की थी, जिसमें सबसे अधिक 96.45त्न की कमी और 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचत दर्ज की गई थी। एमआरपी में सबसे अधिक संख्या में कटौतियां 50त्न से 75त्न के बीच रहीं।

भारत में कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार ने देश भर में खुदरा और अस्पताल फार्मेसियों सहित दवा आपूर्ति की कड़ी में कैंसर रोधी दवाओं के अत्यधिक मार्जिन पर सीमा लगा दी है।

एमआरपी में सबसे अधिक संख्या में कटौतियां 50त्न से 75त्न के बीच रहीं। 650 से अधिक फॉर्मूलेशन में एमआरपी में 50त्न से अधिक की कमी दर्ज की गई। सबसे अधिक कमी 96.45त्न दर्ज की गई (9 नवंबर, 2026 तक)।

इन एमआरपी में कमी के कारण, अनुमानित बचत 3,541 करोड़ रुपये है (9 नवंबर, 2026 तक)। यह अनुमानित वार्षिक बचत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक बेची गई मात्रा पर लागू मूल और संशोधित कीमतों के बीच के अंतर को दर्शाती है।

व्यापार मार्जिन पर यह सीमा कैंसर रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और खरीद मूल्य के बीच अंतर को लेकर राज्य अधिकारियों, रोगियों और नागरिकों की ओर से उठाई गई चिंताओं के उत्तर में निर्धारित की गई है। उपभोक्ता एनपीपीए वेबसाइट और आधिकारिक फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप/पोर्टल दोनों का उपयोग करके दवाओं की संशोधित कीमतों की पुष्टि कर सकते हैं।

व्यापार मार्जिन वह अंतर है जो निर्माता की ओर से स्टॉक रखने वाले/ वितरक से ली जाने वाली कीमत और किसी दवा के लिए रोगी की ओर से भुगतान की जाने वाले अधिकतम मूल्य (एमआरपी) के बीच होता है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं होता है। जब यह व्यापार मार्जिन बहुत अधिक होता है, तो आपूर्ति श्रृंखला में भारी मुनाफा जुड़ जाता है। इससे रोगियों के लिए अंतिम लागत बहुत बढ़ जाती है, जिससे पहले से ही महंगी कैंसर की दवाएं निर्माता की ओर से बेची जाने वाली कीमत से कहीं अधिक महंगी हो जाती हैं।

इस आदेश के अनुसार, प्रत्येक दवा का नया अधिकतम खुदरा मूल्य मार्च 2026 के औसत वितरक मूल्य से निर्धारित किया गया है। उस मूल्य पर व्यापार मार्जिन 30त्न से अधिक नहीं हो सकता है, और उस पर जीएसटी जोड़ा जाएगा।

मरीजों के लिए जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं को अधिक किफायती बनाने के लिए, सरकार औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013 के अंतर्गत दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के जनादेश के अंतर्गत है, जिसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना, मुनाफाखोरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी उपचार किफायती बने रहें।

डीपीसीओ, 2013 के अनुसार दवाओं को दो समूहों में बांटा गया हैः अनुसूचित दवाएं: ये वे दवाएं हैं जो डीपीसीओ, 2013 की पहली अनुसूची में शामिल हैं, जो राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (एनएलईएम), 2022 है। सरकार इनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। एनएलईएम 2022 में 388 दवाएं सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 63 कैंसर रोधी दवाएं हैं। गैर-अनुसूचित दवाएं: ये वे दवाएं हैं जो डीपीसीओ, 2013 की पहली अनुसूची में शामिल नहीं हैं। अनुसूचित दवाओं के उलट, जिनकी अधिकतम कीमत तय होती है, इनका विनियमन मूल्य निगरानी के माध्यम से किया जाता हैः डीपीसीओ, 2013 के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, एक निर्माता बारह महीने में एमआरपी को 10त्न से अधिक नहीं बढ़ा सकता है, और यदि बढ़ोतरी 10त्न से अधिक हो जाती है, तो अगले बारह महीने के लिए कीमत को वापस 10त्न के स्तर पर लाना होगा।

बस्तर में मतदाता सूची पुनरीक्षण शुरू, 11 दिसंबर तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति

एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, जिले में 5.93 लाख से अधिक मतदाता दर्ज

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ

*जगदलपुर,।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बस्तर जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को जिला निर्वाचन कार्यालय सहित जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों एवं मतदान केंद्रों में एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। यह पुनरीक्षण अभियान 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बस्तर जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों के कुल 848 मतदान केंद्रों में



5,93,673 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3,08,274 महिला और 2,85,381 पुरुष मतदाता शामिल हैं। वहीं 18 तृतीय लिंग मतदाताओं के नाम भी सूची में दर्ज हैं। जिले में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है।

विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के 87 मतदान केंद्रों में 64,144 मतदाता दर्ज हैं। बस्तर विधानसभा क्षेत्र के 230 मतदान केंद्रों में 1,63,702, जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 278 मतदान केंद्रों में सर्वाधिक 1,93,041 तथा चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के 253 मतदान केंद्रों में 1,72,786 मतदाता शामिल हैं। इन आंकड़ों में सुकमा जिले के 21 मतदान केंद्र भी शामिल हैं।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम विलोपित कराने अथवा किसी प्रकार का संशोधन कराने के लिए नागरिक 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक अपने दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि जिन पात्र व्यक्तियों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करें। इसके साथ ही 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी भविष्य में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अग्रिम रूप से फॉर्म-6 भर सकते हैं। प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण जांचने की अपील की है।

संपादकीय

लाचारी जैसी स्थिति

इस सदी में भारतीय मध्य वर्ग के विस्तार और उसे सहारा दिए रहने का प्रमुख स्रोत टेक सेक्टर रहा है। वहां अवसर सिकुड़ने और उस स्रोत से आमदनी में गिरावट का सीधा असर उपभोक्ता बाजार पर पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर चिंताजनक है कि इस वर्ष सूचना तकनीक क्षेत्र में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि (अप्रेजल) निराशाजनक रही है। टेक पेशेवरकर्मियों के ऐप ब्लाइंड के सर्वे से सामने आया है कि 35 प्रतिशत कर्मचारियों को या तो कोई वेतन वृद्धि नहीं मिली, या वेतन कटौती का सामना करना पड़ा। इसमें 30 प्रतिशत के वेतन में शून्य बढ़ोतरी हुई, जबकि पांच प्रतिशत की सैलरी घटी। यह सर्वे 2,178 टेक प्रोफेशनल्स को शामिल करते हुए किया गया। इससे सामने आई स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक से पांच प्रतिशत की मामूली वृद्धि को जोड़ लें, तो कुल 59 प्रतिशत कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पांच प्रतिशत या उससे कम रही। 2025 में ऐसे कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 34 प्रतिशत थी। जानकारों के मुताबिक इसका कारण कर्मचारियों का खराब प्रदर्शन नहीं है। बल्कि सर्वे के दौरान 41 प्रतिशत लोगों ने कंपनी की खराब वित्तीय हालत या लागत में कटौती को कारण बताया, जबकि 18 प्रतिशत ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और ऑटोमेशन को जिम्मेदार माना। एआई की लागत सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। कई कंपनियों ने बढ़ते एआई और सर्वर खर्च के कारण कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को फ्रीज कर दिया है। इस घटनाक्रम का असर बेशक कर्मचारियों की संतुष्टि पर पड़ रहा है। ये बात ब्लाइंड सर्वे से भी सामने आई है। इसका असर आने वाले समय में उनके प्रदर्शन पर पड़ सकता है, जिसका एक नतीजा उनकी नौकरी का खतरे में पड़ना होगा। दरअसल, सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें अब वेतन वृद्धि से ज्यादा छंटनी का डर सता रहा है। लेकिन बात सिर्फ उन कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी। इस सदी में भारतीय मध्य वर्ग के निर्माण, विस्तार और उसे सहारा दिए रहने का प्रमुख स्रोत टेक सेक्टर रहा है। वहां अवसर सिकुड़ने और इस स्रोत से होने वाली आमदनी में गिरावट का सीधा असर उपभोक्ता बाजार पर पड़ेगा, जिससे पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इस आशंका को लेकर काफी समय से चेतावनी दी जाती रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके बावजूद लाचारी जैसी स्थिति बनी हुई है।

डिजिटल दासता में आम नागरिक का संकट

विकेश कुमार बडोला



ऑनलाइन एवं साइबर ठगी का एक गोपनीय तंत्र भी देश-दुनिया में बुरी तरह से सक्रिय रहा है और अब भी सक्रिय है, जिस पर लाख प्रयासों के बाद भी भारत एवं अन्य देश स्थायी नियंत्रण करके उसे समाप्त नहीं कर पाए हैं। यह तंत्र देश के सज्जन नागरिकों को ऑनलाइन ठगी के जाल में फांसता है लोकतंत्र की बातें ही बातें होती रही हैं, मगर अभी तक तंत्र करदाताओं के रूप में उपस्थित लोगों की सुविधा नहीं बन सका है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विभीषिका है। यह कैसी विडंबना है कि हिंदू समाज का प्रत्येक परिवार तो अधिक से अधिक एक या दो ही बच्चों तक सीमित है, किंतु पूरे देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह विरोधाभास न केवल लोकतंत्र अपितु लोकतंत्रगत अनेक नीतियों के समुचित संचालन के लिए बड़ी बाधा है। दुर्भाग्य से इस दिशा में तंत्र के सभी कार्यकारी स्तंभ विचारशून्य हैं। भारतीय तंत्र की ऐसी ही एक विरोधाभासी नीति है डिजिटल इंडिया। पहले धीरे-धीरे और तीव्रतापूर्वक यह नीति दासता की समस्या बन चुकी है। गत 21 सितंबर 2026 को शासन के दूरसंचार विभाग ने फर्जी तरीके से सिम जारी करने, दूरसंचार पहचान संख्या यानी मोबाइल नंबर के गलत इस्तेमाल और मोबाइल के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ को लेकर एक सार्वजनिक परामर्शिका जारी की। विभाग के अनुसार ऐसे प्रकरणों में दंड के रूप में 3 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक अर्थदंड हो सकता है, इसलिए उपभोक्ता अपने स्तर पर भी सावधानी बरतें। यह परामर्शिका विभाग ने तब निकाली जब मध्य प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र में फर्जी तरीके से सिम जारी किए जाने से संबद्ध एक प्रकरण का पता चला। इस प्रकरण में साइबर अपराध का संदर्भ लेकर की गई जांच में ज्ञात हुआ कि छत्तीसगढ़ में एक 'प्वाइंट ऑफ सेल एजेंट' ने नागरिकों के दस्तावेजों का उनकी जानकारी और सहमति के बिना इस्तेमाल कर 25 मोबाइल कनेक्शन जारी कर दिए। इसके बाद दूरसंचार विभाग और संबंधित दूरसंचार कंपनियों ने पीओएस एजेंट को कालीसूची में डाल दिया। इस घटना के पश्चात दूरसंचार विभाग ने कुछ सभी के लिए कुछ सतर्कता निर्देश जारी किए हैं। एक, फर्जी दस्तावेज पर सिम न लें। दो, अपने नाम पर जारी सिम किसी दूसरे व्यक्ति को न दें, बेचें अथवा किराये पर न दें। तीन, साइबर अपराध, गैर-कानूनी गतिविधि के लिए सिम उपलब्ध न कराएं। चार, आईएमईआई नंबर में परिवर्तन करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल न करें। पांच, मोबाइल एप, वेबसाइट या किसी अन्य माध्यम से कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) या अन्य दूरसंचार पहचान संख्या में बदलाव न करें। छह, संचार साथी से सिम की जांच करें। सात, नागरिक पर जाकर इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा संचार साथी मोबाइल एप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे दिशानिर्देश जारी करते हुए दूरसंचार विभाग ने जो विचित्र घोषणा की है वो यह है कि सिम के गलत इस्तेमाल पर मूल ग्राहक भी उत्तरदायी होगा। इस घोषणा से सिद्ध हो गया है कि इस देश का आम नागरिक पूरी तरह डिजिटल दासता से घिर चुका है। ऐसे में जब नागरिकों के मोबाइल फोन पर अनेक एप्स डाउनलोड हैं और इच्छा के साथ अथवा विवशतापूर्वक वह विभिन्न सेवाओं के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है, तो इनके प्रौद्योगिकीय संचालन, पासवर्ड, कीवर्ड, आईडी व अन्य पहचानों की व्यक्तिगत सुरक्षा, गोपनीयता एवं निजता वह कैसे प्रबंधित करेगा। देश का हरेक आम नागरिक तो सॉफ्टवेयर या एप्स की एचटीएमएल यानी कूट भाषा का विशेषज्ञ नहीं है, जो वह साइबर ठगों द्वारा अपने मोबाइल फोन के नंबरों या किसी एप्स के पासवर्ड या अन्य कीवर्ड के गलत इस्तेमाल की पूर्व जानकारी, पूर्व सूचना व पूर्वाभास प्राप्त कर लेगा। जब मोबाइल फोन के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवसाय, बैंक, पहचान, गैस, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य क्षेत्रों की जानकारी इंटरनेट की सार्वजनिक दुनिया में उपलब्ध है, तो साइबर ठगों से साधारण व्यक्ति साइबर विशेषज्ञ हुए बिना कैसे सुरक्षित हो सकता है! मोबाइल फोन पर वीडियो तथा अन्य चीजें देखने, सुनने एवं अपनाने की आदत तो शासन ने लोगों को उनकी अनुमति-सहमति के बिना लगा ही दी है। बाकायदा इसके लिए लोगों से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है। ऐसी आदत के बाद लोगों की स्मृति कमजोर हो रही है। उनकी स्मरणशक्ति दिन-प्रतिदिन कम हो रही है। डिजिटल दासता से घिरकर अपनी ऐसी स्थिति में भला आम आदमी साइबर ठगी के प्रति उस स्तर का जागरूक व्यक्ति कैसे हो सकता है, जैसे शासन उससे अपेक्षा कर रहा है! तंत्र में दूरसंचार विभाग के शासन का यह कैसा खेल है, जिसमें वह अपने संचालन हेतु प्रतिनिधियों अर्थात नेताओं के चुनाव के लिए तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक के चुनाव करवाता है, किंतु अपने चुनावी घोषणापत्रों के अतिरिक्त, आकस्मिक रूप से बनने वाली नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए कभी भी जनता की सलाह, सहमति या अस्वीकृति का देशव्यापी अभियान नहीं चलाता है। उदाहरण के लिए जब देश में दूरसंचार की नीति बनी और इसका क्रियान्वयन आरंभ हुआ तो जनता से इस बारे में कुछ नहीं पूछा गया कि उन्हें दूरसंचार की अवसंरचना चाहिए अथवा नहीं। भौतिक वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करने के लिए लालायित जनता, दीर्घावधि में प्रकट ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के नवोन्त वैज्ञानिक रूप के व्यक्ति, परिवार व समाज पर पडने वाले दुष्प्रभावों से अनभिज्ञ होती है। ऐसा ही दूरसंचार सेवा के विषय में भी हुआ। आज दूरसंचार सेवा केवल संदेश सेवा तक ही सीमित नहीं रही। यह मोबाइल फोन के माध्यम से बहुसंचारक प्रणाली में परिवर्तित हो चुकी है। अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट की तीव्र गति के कारण अनेक सॉफ्टवेयर कंपनियां विविध प्रकार के अनुप्रयोग (एप्लिकेशन्स) बना रहे हैं, जिनके माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार की सरकारी, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे अनुप्रयोग, सेवा प्रदान करने वाले सरकारी एवं निजी संस्थानों के विशिष्ट सॉफ्टवेयर से संबद्ध होते हैं और आरंभ में नि:शुल्क तथा कालांतर में सशुल्क लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यह कार्यक्रम विगत दस-पंद्रह वर्षों में अत्यधिक तेजी से बढ़ा है। आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकियों में भारत से अधिक उन्नत अमेरिका, चीन एवं अन्य देशों में ऐसे कार्यक्रम 10-15 वर्षों से भी बहुत पहले से आरंभ हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो दूरसंचार सेवा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोबाइल फोन, सिम कार्ड तथा दोनों संसाधनों के क्रयार्थ व्यक्तिगत पहचान-पत्रों की आवश्यकता होती है। दोनों ही संसाधनों पर व्यक्ति का धन व्यय होता है। इन दोनों के संयुक्त हो जाने पर प्राप्त होने वाली दूरसंचार एवं बहुसंचारण सेवाओं के लिए व्यक्तियों को अपने प्रामाणिक पहचान-पत्र सेवा प्रदाता कंपनियों एवं उनके खुदरा व्यापारियों के पास जमा करने होते हैं। सिम कार्ड से संचालित मोबाइल फोन के नंबर व्यक्तियों के बैंक खातों से भी जुड़ चुके हैं। ऐसे में ऑनलाइन एवं साइबर ठगी का एक गोपनीय तंत्र भी देश-दुनिया में बुरी तरह से सक्रिय रहा है और अब भी सक्रिय है, जिस पर लाख प्रयासों के बाद भी भारत एवं अन्य देश स्थायी नियंत्रण करके उसे समाप्त नहीं कर पाए हैं। यह तंत्र देश के सज्जन नागरिकों को ऑनलाइन ठगी के जाल में फांसता है। ऐसे अनेक प्रकरण देश में पहले ही घटित हो चुके हैं। किंतु दुर्भाग्य से इस पर स्थायी नियंत्रण की दिशा में शासन के अभियान विफल ही सिद्ध हुए हैं। ऑनलाइन ठगी का सबसे विलक्षण तरीका है, दूरसंचार सेवा पाने के लिए दूरसंचार कंपनियों के मूल एवं फुटकर सेवा प्रदाताओं के पास सिम खरीद हेतु जमा किए गए व्यक्तियों के विभिन्न पहचान-पत्र, जिन्हें चोरी किया जाता है। लोकतंत्र का यह अर्थ तो कदापि नहीं हो सकता है कि आम लोगों को सरकारी कामों का भी उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए।

आलेख

दंतेवाड़ा के सुदूर 'लावा' गाँव में पहली बार गूंजी टीवी की आवाज,क्रेडा और जिला प्रशासन की अनूठी पहल

धनंजय राठौर, आमना खान

छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों में विकास का पहिया अब तेजी से घूमने लगा है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले एक अत्यंत सुदूर और दुर्गम पहाड़ी गाँव %लावा% में जिला प्रशासन के सहयोग से क्रेडा (क्रेडा) विभाग द्वारा %कम्युनिटी सोलर टीवी% (सामुदायिक सौर टीवी) की स्थापना की गई है। महज़ 21 परिवारों की आबादी वाले इस छोटे से आदिवासी गाँव के लिए यह किसी ऐतिहासिक क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने अपने जीवन में पहली बार गाँव के भीतर ही टेलीविज़न स्क्रीन देखी है। बस्तर के दूरदराज गाँवों तक विकास और खुशहाली पहुँचाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अभूतपूर्व पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर के हमारे दूरदराज और अंतिम छोर पर बसे गाँवों तक विकास, शिक्षा, और आधुनिक तकनीक की रोशनी पहुँचाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दंतेवाड़ा के सुदूर लावा गाँव में सामुदायिक सोलर टीवी की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि विकास अब नक्सलवाद के अंधेरे को पीछे छोड़कर हर आदिवासी भाई-बहन के जीवन तक पहुँच रहा है। जब इन सुदूर इलाकों के बच्चे और ग्रामीण पहली बार टीवी स्क्रीन पर देश-दुनिया की खबरें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखेंगे, तो उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। हमारी सरकार बस्तर के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैलाडीला की ऊँची पहाड़ियों के पीछे और घने जंगलों के बीच बसा लावा गाँव भौगोलिक रूप से बेहद अलग-थलग है। किरंदुल के मुख्य लौह-अयस्क खनन क्षेत्र से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित इस गाँव तक पहुँचने के लिए आज भी कोई पक्की सड़क नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों, जैसे राशन दुकान से चावल लाने के लिए आज भी पहाड़ी और पथरीले रास्तों से होकर मीलों पैदल सफर तय करना पड़ता है। लावा और इसके आसपास का पुरेंगल क्षेत्र दशकों तक घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों का फायदा उठाकर नक्सलियों ने इस क्षेत्र को अपना गढ़ बना रखा था, जिसके कारण कई सालों तक यहाँ न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँच पाता था और न ही कोई जनप्रतिनिधि। सुरक्षा कारणों से यह गाँव पूरी तरह से आधुनिक दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ बुनियादी सुविधाओं का पहुँचना एक सपना बना हुआ था।सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन्स और मुस्तैदी के बाद अब इस क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है। जहाँ कभी दहशत का माहौल था, वहाँ अब बदलाव की बयार बह रही है। हाल के दिनों में जिला कलेक्टर और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने खुद इस गाँव का दौरा कर ग्रामीणों की चौपाल ली। सुरक्षा और विश्वास के इसी माहौल का नतीजा है कि आज प्रशासन सीधे ग्रामीणों के दरवाज़े तक विकास योजनाएँ पहुँचा रहा है। चूँकि यह गाँव पारंपरिक बिजली ग्रिड से काफी दूर है, इसलिए जिला प्रशासन और क्रेडा (छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण) ने यहाँ सौर ऊर्जा का सहारा लिया। गाँव में लगाए गए इस कम्युनिटी सोलर टीवी के जरिए अब निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलेंगे: दुर्गम पहाड़ी गाँव %लावा% में टीवी के माध्यम से अब गांव के लोग छत्तीसगढ़, भारत और पूरी दुनिया में हो रही गतिविधियों और खबरों से सीधे जुड़ सकेंगे। इससे ग्रामीणों को सरकार की नई योजनाओं, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के बारे में आसानी से पता चल सकेगा। गांव के बच्चों को अब टीवी के माध्यम से मनोरंजन के साथ पढ़ाई, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जिससे उनकी समझ और सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले इन बच्चों के लिए स्क्रीन पर देखकर सीखना एक नया और प्रभावी अनुभव होगा। कम्युनिटी टीवी होने के कारण गांव के सभी 21 परिवार एक जगह इकट्ठा होकर कार्यक्रम देख सकेंगे। इससे ग्रामीणों के बीच आपसी जुड़ाव और बढ़ेगा। दिनभर खेती और वनोपज इकट्ठा करने की कड़ी मेहनत के बाद, शाम को मनोरंजन के साधन मिलने से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। चूंकि यह इलाका बेहद सुदूर और बिजली की पारंपरिक लाइनों से दूर है, इसलिए सोलर पैनल आधारित टीवी पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे बिना बिजली कटौती की चिंता अपना कामकाज कर सकते हैं।

पीएम-सेतु:भारत के आईटीआई में बदलाव का एक वर्ष

पीएम-सेतु का उद्देश्य हब-एंड-स्पोक मॉडल और उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण के माध्यम से 1,000 सरकारी आईटीआई का अत्याधुनिकरण करना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों के माध्यम से पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाने का भी प्रावधान है। रणनीतिक निवेश योजनाओं, विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) और एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स के माध्यम से उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस योजना में उभरती प्रौद्योगिकियों और व्यवसायों से संबंधित नए दौर के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। चयनित एनएसटीआई में उन्नत कौशल प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां भी सहयोग प्रदान कर रही हैं। राज्य स्तरीय संचालन समितियों और उद्योग की भागीदारी के माध्यम से राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में इसके कार्यान्वयन का भी विस्तार किया गया है। एक वर्ष की प्रगति के तहत 850 आईटीआई की पहचान और 14 आईटीआई क्लस्टरों को मंजूरी शामिल है। प्रस्तावित कौशल प्रयोगशालाएं छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव के अवसरों को और बढ़ाएंगी। भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) देश के व्यावसायिक प्रशिक्षण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये युवाओं को रोजगार और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक कौशल प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे कार्यबल की आवश्यकताएं बदल रही हैं, वैसे-वैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और उद्योगोन्मुखी स्वरूप को मजबूत करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में, पीएम-सेतु (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई) को 4 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया। यह योजना सरकारी आईटीआई को आधुनिक और उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण संस्थानों में परिवर्तित करके व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाती है। इस पहल का उद्देश्य उद्योग-नेतृत्व वाले शासन को मजबूत करना, प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन करना और कार्यबल की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप मांग-आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। योजना का कुल परिव्यय ?60,000 करोड़ है, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से 30,000 करोड़ रुपये, राज्यों की ओर से 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग की ओर से 10,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह योजना 4 अक्टूबर 2026 को एक वर्ष पूरा कर रही है। आईटीआई: कुशल कार्यबल की नींव तैयार करना आईटीआई युवाओं को रोजगार और उद्योग के लिए व्यावहारिक कौशल से लैस करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेड के आधार पर पाठ्यक्रम की अवधि छह महीने से दो वर्ष तक होती है। प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वय के लिए जिम्मेदार शीर्ष संगठन है। इसके कार्यों में नीतियों, मानदंडों और मानकों का निर्धारण, पाठ्यक्रम विकास, संबद्धता, अनुदेशक प्रशिक्षण और ट्रेड परीक्षण शामिल हैं। आईटीआई राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन हैं। देश में सरकारी और निजी आईटीआई सहित आईटीआई की कुल संख्या 2014 में 9,776 से बढ़कर 2026 में 13,888 हो गई है, जो 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसके अलावा, देशभर के आईटीआई में नामांकन शैक्षणिक सत्र 2014ङ्क15 में 9.51 लाख से बढ़कर शैक्षणिक सत्र 2025ङ्क26 में 14.70 लाख हो गया है, जो 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विस्तारित होता यह नेटवर्क व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप इसे ढालने के लिए एक व्यापक संस्थागत आधार प्रदान करता है। पीएम-सेतु बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योग की भागीदारी और नए दौर के प्रशिक्षण को एक साथ लाकर व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करता है। यह परिवर्तन दो अलग-अलग घटकों पर आधारित है, जिसमें पहला घटक सरकारी आईटीआई पर और दूसरा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) पर केन्द्रित है। घटक-1 में 1,000 सरकारी आईटीआई शामिल हैं, जिनमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई हैं। इन संस्थानों का आधुनिक बुनियादी ढांचे और उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण के साथ हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक हब औसतन चार स्पोक से जुड़ा है, जिससे उन्नत बुनियादी ढांचे, आधुनिक ट्रेडों, डिजिटल शिक्षण प्रणालियों और इनक्यूबेशन सुविधाओं तक साझा पहुंच संभव हो रही है। हब में नवाचार केन्द्र, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचा, उत्पादन इकाइयां और प्लेसमेंट सेवाओं जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्पोक प्रशिक्षण तक पहुंच का विस्तार करते हैं और शिक्षार्थियों को अपने-अपने क्लस्टरों में उपलब्ध संसाधनों से जोड़ते हैं। यह मॉडल स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल सामग्री और उद्योग-अनुरूप पाठ्यक्रमों के माध्यम से आईटीआई के उन्नयन में सहायता कर रहा है। घटक-2 भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाने पर केन्द्रित है। इसमें क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से प्रशिक्षकों का उन्नत प्रशिक्षण शामिल है। संबंधित राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश उद्योग के परामर्श से पीएम-सेतु के तहत आईटीआई के चयन का नेतृत्व करते हैं।

महंगाई की तपिश में फीके पड़ते त्योहार

अनुज आचार्य

राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि उस दिन दिखाई देगी जब मेहनतकश परिवार अपनी कमाई से सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सके, बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर सके और महीने का अंत आर्थिक चिंता के बजाय सुरक्षा की भावना के साथ कर सकें, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होगी इन दिनों जब भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की थाली से स्वाद, परिवार के सपनों से सुकून और मेहनतकश इनसान की जिंदगी से वह छोटी-सी खुशहाली भी छीनती शुरू कर दी है, जिसके सहारे वह हर दिन बेहतर कल की उम्मीद में जीता है। महंगाई केवल कीमतों का बढना नहीं, बल्कि आम आदमी की क्रयशक्ति, आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन पर पडने वाला दबाव है। महंगाई की इस चुनौती को अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। 23 अक्टूबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और समुद्री व्यापार मार्गों पर संकट ने तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आयात पर काफी निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महंगे तेल से आयात बिल बढ़ता है और पेट्रोल-डीजल, माल ढुलाई, कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक गतिविधियों की लागत पर दबाव पड़ता है। परिवहन महंगा होने पर सब्जियों, फलों, दूध और अनाज को बाजार तक पहुंचाने का खर्च भी बढ़ जाता है। इस प्रकार तेल की कीमतों में लगी आग अंतत: आम आदमी की रसोई तक पहुंचने का खतरा पैदा करती है। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 12 अक्टूबर 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढक़र 5.54 प्रतिशत हो गई, जबकि अगस्त में यह 4.83 प्रतिशत थी। खाद्य महंगाई भी अगस्त के 5.97 प्रतिशत से बढक़र सितंबर में 7.74 प्रतिशत पहुंच गई। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 6.08 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 4.88 प्रतिशत रही। खाद्य महंगाई की दर ग्रामीण क्षेत्रों में 8.06 प्रतिशत दर्ज की गई। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का दबाव विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों के बजट को प्रभावित कर रहा है। सीमित आय वाले परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भोजन, आवास और परिवहन पर खर्च करते हैं। ऐसे में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मामूली वृद्धि भी उनकी बचत को समाप्त कर देती है। मध्यम वर्ग के लिए भी स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी जरूरतें लगातार अधिक खर्च मांगती हैं। आर्थिक समस्याएं इस समस्या को और गंभीर बनाती हैं। मैं स्वयं उपभोक्ता हूं और देखता हूं कि खुद मेरे शहरों बैजनाथ-पपरोला में खाद्य पदार्थों/सब्जी इत्यादि के दामों पर प्रशासन का कोई चेक नहीं है और न ही प्रशासनिक उच्च अधिकारी/खाद्य नियंत्रक कभी बाजार जाकर रेटलिस्ट की जांच करते हैं। यही वजह है कि सभी विक्रेता मनमर्जी के रेट लगाकर ग्राहकों को लूट रहे हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी को राष्ट्रीय आय का लगभग 57.7 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जबकि निचली 50 प्रतिशत आबादी के हिस्से में केवल 15 प्रतिशत आय आती है। देश की लगभग 65 प्रतिशत संपत्ति शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों के पास केंद्रित है। दूसरी ओर, विश्व बैंक के अक्टूबर 2025 के आकलन के अनुसार, प्रतिदिन तीन डॉलर की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा पर भारत में गरीबी का अनुपात 2011-12 के 27.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 5.3 प्रतिशत रह गया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन गरीबी में कमी और आर्थिक असमानता समाप्त होना अलग-अलग बातें हैं। विकास की असली सफलता तभी होगी, जब आर्थिक प्रगति का लाभ व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचे। महंगाई के लिए केवल सरकार या व्यापारियों को दोषी ठहराना भी समस्या का पूरा समाधान नहीं है। किसान बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी और डीजल पर बढ़ते खर्च से जूझता है। मौसम की मार उसकी फसल और आमदनी दोनों को प्रभावित करती है। खेत से उपभोक्ता तक पहुंचने के बीच भंडारण, परिवहन, पैकेजिंग और खुदरा बिक्री की लागत भी जुड़ती है। इसलिए किसान को उचित मूल्य और उपभोक्ता को वाजिब कीमत दिलाने के लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता जरूरी है। व्यापारी का उचित लाभ कमाना उसका अधिकार है, लेकिन जमाखोरी, कृत्रिम अभाव, गलत माप-तौल और अनुचित मुनाफाखोरी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा उपभोक्ता संरक्षण और माप-तौल संबंधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करें। बाजारों में मूल्य सूची प्रदर्शित करवाना, बिल देना सुनिश्चित करना, शिकायतों की जांच करना और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर कार्रवाई करना जरूरी है।



संक्षिप्त समाचार

पलगडी गांव में 15 दिनों तक से चलाया गया नशामुक्ति अभियान, जागरूकता रैली निकालकर ग्रामीणों को दिलाई गई शराबबंदी की शपथ सूचना देने वालों को मिलेगा नकद इनाम



सरगुजा। सरगुजा जिले के आकांक्षी विकासखंड लखनपुर के पलगड़ी गांव को नशामुक्त बनाने और शराबखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से पिछले 15 दिनों से चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्रामीणों ने एक अनूठी पहल की है। नशामुक्ति को लेकर गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को शराब के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। इसके बाद ग्रामवासियों को गांव में शराबबंदी बनाए रखने की शपथ दिलाई गई।नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्रामसभा में निर्णय लिया गया कि गांव में शराब बनाने और पीने वालों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। ग्राम सभा के निर्णय अनुसार गांव में शराब बनाने पर 6 हजार रुपये, शराब पीने पर 5 हजार रुपये तथा शराब बनाने और शराब पीकर गांव में आने वाले लोगों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 2 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।ग्रामीणों का उद्देश्य गांव में नशे पर अंकुश लगाना, सामाजिक वातावरण को बेहतर बनाना तथा परिवारों को शराब से होने वाले नुकसान से बचाना है। इस पहल को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सहयोग करने का संकल्प लिया। लखनपुर विकासखंड के ग्राम कुंवरपुर कंचनपुर केवरी गोरता के बाद अब पलगड़ी में गांव में पूर्ण शराबबंदी की गई है। इस दौरान सरपंच सुरचना सिंह, सचिव अनिल गुप्ता, उपसरपंच सोनमती प्रजापति, पूर्व सरपंच सूरज सिंह, स्व-सहायता समूह की दीदियां सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम और सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा के मुख्य आतिथ्य में विकासखंड स्तरीय करमा महोत्सव संपन्न



बलरामपुर। जनजातीय संस्कृति, लोककला और परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से जिले के विकासखंडों में विकासखंड स्तरीय करमा महोत्सव का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। जनपद पंचायत रामचंद्रपुर में आयोजित महोत्सव में प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं शंकरगढ़ के स्व. लरंग साय स्टेडियम और राजपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (महुआपारा) खेल मैदान में हुए आयोजनों में सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि रहीं। महोत्सव में पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने मांदर की थाप पर करमा नृत्य और लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दीं। लोकधुनों की लय और कलाकारों के उत्साह ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया, जिसका दर्शकों ने तालियों से उत्साहवर्धन किया। उल्लेखनीय है कि उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव (करमा महोत्सव) 2026 ग्राम पंचायत, विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। विकासखंड स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले दल जिला स्तरीय महोत्सव में प्रस्तुति देंगे। जिला स्तर के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें राज्य स्तर पर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा।

कलेक्टर और एसएसपी ने छठ घाट का किया निरीक्षण, आयोजन समिति के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा

कलोआस्था और उल्लास के साथ मनेगा छठ पर्व,अरपा तट पर तैयारियां तेज

■ श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा का रखें विशेष ध्यान— कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल

बिलासपुर। लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के आयोजन को लेकर अरपा नदी स्थित छठ घाट पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस वर्ष 13 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाले पर्व के लिए आयोजन समिति और नगर निगम द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल और एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट पर आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और पर्व के सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में चर्चा की। अरपा तट स्थित छठ घाट पर प्रतिवर्ष बिलासपुर सहित आसपास के शहरों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सूर्योपासना, स्नान और अर्घ्य अर्पण के लिए जुटने वाले श्रद्धालुओं से घाट पर आस्था और उत्साह का वातावरण बनता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संभावित उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन, नगर निगम और आयोजन समिति के समन्वय से तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि छठ पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, स्वच्छता और अनुशासन का संदेश देता है। श्रद्धालु पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ घाट पर आते हैं। उनकी सुविधा और सम्मान का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने घाट की साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश, सुरक्षित आवागमन, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखने तथा सभी तैयारियां समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नदी में उतरने वाले



स्थानों को सुरक्षित बनाया जाए और गहरे पानी वाले हिस्सों में श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के लिए स्पष्ट संकेत एवं आवश्यक अवरोध लगाए जाएं। घाट पर प्राथमिक उपचार और आपात सहायता की व्यवस्था रहे। उन्होंने आयोजन समिति के स्वयंसेवकों और संबंधित विभागों के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखने को कहा, ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता मिल सके। एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने कहा कि श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा-अर्चना कर सकें, इसके लिए पुलिस की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। घाट तक आने-जाने के मार्गों, प्रवेश एवं निकास स्थलों और भीड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यातायात और पार्किंग की व्यवस्था इस तरह की जाए कि श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा न हो और आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध रहे। उन्होंने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों और पार्किंग स्थलों का उपयोग करने, बच्चों को साथ रखने तथा पुलिस एवं स्वयंसेवकों के निर्देशों का पालन करने की अपील की। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री प्रवीण झा ने कहा कि अरपा तट का छठ आयोजन श्रद्धा के साथ सामाजिक सहभागिता का भी प्रतीक है। समिति का प्रयास है कि प्रत्येक श्रद्धालु को सुविधाजनक वातावरण में पूजा-अर्चना का अवसर मिले। प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति के स्वयंसेवक घाट पर श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन और सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से नदी और घाट की स्वच्छता बनाए रखने तथा पूजन सामग्री निर्धारित स्थानों पर रखने की अपील की। बैठक में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और आयोजन समिति के समन्वय से पर्व को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया गया।

कुर्मे बांध में नहाने गया 22 वर्षीय युवक गहरे पानी में डूबा मौत.....

लखनपुर। लखनपुर थाना क्षेत्र के कुन्नी पुलिस चौकी अंतर्गत तीरकेला कुर्मे बांध में नहाने के दौरान एक 22 वर्षीय युवक के गहरे पानी में डूबने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक की तलाश के लिए मंगलवार सुबह एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर खोजबीन में शुरू की 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफकी टीम ने गहरे पानी से दोपहर 12.30 बजे युवक के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद कुन्नी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द किया है और मार्ग काम करते हुए मामले की जांच की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रबिल खलखो पिता जुग साय खलखो, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम तीरकेला 9 नवंबर दिन सोमवार दोपहर बैलों



को दाना खिलाने से पहले अपने साथियों के साथ कुर्मे बांध में मवेशियों को नहलाने गया था। मवेशियों को नहलाने के बाद युवक स्वयं नहाने के लिए बांध के गहरे पानी में उतर गया। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते पानी में डूब गया।घटना की जानकारी मिलने पर युवक के परिजनों एवं ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। मामले की शिकायत कुन्नी पुलिस चौकी में की गई। शाम होने के कारण 10 नवंबर दिन मंगलवार सुबह एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने गहरे पानी से युवक केशव को बाहर निकाला पुलिस ने सब का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द किया है इधर पुलिस मर्ग कायम करते हुए मामले की जांच में जुटी है वहीं घटना के बाद से परिवारजनों में शोक का माहौल व्याप्त है।

इन्द्रावतीपुर में खैरवार समाज के सामुदायिक भवन का भूमिपूजन,कृषि मंत्री नेताम ने पूरा किया वादा...

बलरामपुर। रामचंद्रपुर विकासखंड के चरकपथली-इन्द्रावतीपुर-सनावल में खैरवार, खेरवार, खरवार समाज की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई। प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने अपने वादे के अनुरूप 25 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का विधि-विधान से भूमिपूजन किया। इस अवसर पर करमा महोत्सव एवं जनजातीय गौरव दिवस समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री श्री नेताम अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा नेताम के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समाज के प्रबुद्धजनों और ग्रामीणों ने भवन की सौगात के लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया। यह भवन केवल खैरवार समाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्र के सभी वर्गों के लोग इसका उपयोग



बैठकों, आयोजनों और सामाजिक कार्यों के लिए कर सकेंगे। इससे आपसी सद्भाव और भाईचारे को बल मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री नेताम ने कहा कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी एकता और जागरूकता में होती है। उन्होंने समाज से संगठित होकर आगे बढ़ने और व्याप्त कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ परिवार से ही सशक्त समाज बनता है, इसलिए महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। ग्रामीणों से उन्होंने अपील की कि बीमारी की स्थिति में नजदीकी प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचकर ही उपचार कराएँ, जहाँ शासन ने योग्य चिकित्सक और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। क्षेत्र के विकास पर उन्होंने बताया कि बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और बिजली, सड़क सहित अधोसंरचना के अनेक कार्य प्रगति पर हैं।

मनेंद्रगढ़ में 8.68 करोड़ की लागत से बनेगा नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास.....

एमसीबी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मनेंद्रगढ़ को एक बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और युवाओं को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में 8 करोड़ 68 लाख 35 हजार रुपये की लागत से प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस संस्थान के शुरू होने से क्षेत्र के युवाओं और युवतियों को नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल मानव संसाधन तैयार करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। नर्सिंग कॉलेज के निर्माण को क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे मनेंद्रगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूर-दराज के शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार और करियर के नए अवसर भी विकसित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिला एमसीबी के श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्रा पर रवाना करने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं की अमृतसर स्थित पवित्र श्री हरमंदिर साहिब एवं वैष्णो माता मंदिर की तीर्थयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों एवं पात्र श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों की धार्मिक आस्था को सम्मान देते हुए उन्हें तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान करना है।

जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव में मांदर की थाप पर थिरके आदिवासी कलाकार,करमा नृत्य ने मोहा मन

लखनपुर। जनजातीय गौरव सप्ताह के अवसर पर गोला मुट्ठी संगठन एवं आशा ज्योति निवास सोशल सेंटर लखनपुर के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम लोसंगा स्थित धान खरीदी केंद्र मैदान में जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव 'आदिवासी महातिहार' का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज की गौरवशाली परंपराओं, लोक संस्कृति और प्राचीन विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन करना तथा नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान से परिचित कराना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज रहे। पारंपरिक कर्मा गीतों और मांदर की थाप के बीच नृत्य करते हुए कलाकारों ने विधायक का आत्मीय स्वागत किया। पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार हाथ धुलाकर उन्हें कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश कराया गया। इसके पश्चात मैदान में स्थापित करम वृक्ष की डाल के नीचे विधायक ने विधिवत पूजा-अर्चना की। कार्यक्रम का



शुभारंभ आदिवासी समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उपस्थित अतिथियों का बैच लगाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। महोत्सव में गोला मुट्ठी संगठन द्वारा आदिवासी संस्कृति पर आधारित विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए थे। इनमें पारंपरिक दलहन, तिलहन, कृषि कार्यों में उपयोग किए जाने वाले प्राचीन औजार तथा जनजातीय समाज के पारंपरिक खानपान की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। विधायक प्रबोध मिंज ने सभी स्टॉलों का अवलोकन कर जनजातीय जीवनशैली और परंपराओं की सराहना की। इस अवसर पर विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता के हितों के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और गौरव के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बाहुल्य एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए सरकार द्वारा सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पहुंचविहीन क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों की मांग पर कई छोटी-बड़ी सड़क परियोजनाओं सहित अन्य विकास कार्यों को भी स्वीकृति दिलाई गई है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान विभिन्न पंचायतों से पहुंचे कर्मा नृत्य दलों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई।

बिलासपुर में 15 नवंबर से 154 केंद्रों पर धान खरीदी,तैयारियां अंतिम चरण में

■ 14 नए केंद्र खुलने से किसानों को मिलेगी सुविधा; वास्तविक किसानों को लाभ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता—कलेक्टर

■ छोटे किसानों को पहले अवसर, नोडल अधिकारी 36 बिंदुओं पर तैयारियां जांचकर देंगे रिपोर्ट

बिलासपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप बिलासपुर जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष 14 नए खरीदी केंद्र बढ़ने के साथ जिले के कुल 154 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान खरीदा जाएगा। केंद्रों में खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। शासन इसके लिए बड़ी राशि खर्च करता है, ताकि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार आए। उन्होंने निर्देश दिए कि अपनी मेहनत की उपज बेचने आने वाले वास्तविक किसानों को केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका का आधार है। धान खरीदी किसानों की वर्षभर की मेहनत को आर्थिक संबल देती है। इससे प्राप्त आय खेती की अगली तैयारी के साथ बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतों और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा



करने में मददगार होती है। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से गांवों के बाजार और स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है। ऐसे में सुव्यवस्थित और पारदर्शी धान खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कलेक्टर ने प्रत्येक खरीदी केंद्र में किसानों के बैठने, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सभी केंद्रों के लिए जिला प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में खरीदी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे और किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सीधे उन्हें अवगत कराएंगे। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को 15 नवंबर से पहले संबंधित केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियां पूर्ण होने की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में शासन की निर्धारित चेकलिस्ट के सभी 36 बिंदुओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी। बैठक में बताया गया कि खरीदी केंद्रों में बारदाने पहुंच चुके हैं। इनमें आधे नए और आधे पुराने बारदाने हैं। कलेक्टर ने बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए धान को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था पहले से करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 नवंबर को जिले के सभी 154 केंद्रों में खरीदी प्रारंभ की जाएगी। बाहरी धान की आवक रोकने के लिए मंडी और वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। इन स्थानों पर वाहनों के प्रवेश और उनमें लदी सामग्री की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि वे अपनी ऋण पुस्तिका किसी अन्य व्यक्ति को न दें, ताकि उसका दुरुपयोग न हो और धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को ही मिले। कलेक्टर ने पिछले वर्ष धान बेचने वाले ऐसे किसानों से संपर्क करने के निर्देश भी दिए, जिनका इस वर्ष अब तक पंजीयन नहीं हो पाया है। उन्होंने इन किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में बताया गया कि टोकन की व्यवस्था ऑनलाइन और समिति स्तर, दोनों माध्यमों से रहेगी। 70 प्रतिशत टोकन 'तुहर टोकन' ऐप के माध्यम से और 30 प्रतिशत समिति स्तर से जारी किए जाएंगे। धान खरीदी में छोटे किसानों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने अन्य लंबित प्रकरणों के साथ सीएम हेल्पलाइन, पीएम सूर्यघर योजना, पारस पोर्टल, जनगणना कार्य तथा अधिकारियों द्वारा छात्रावासों के निरीक्षण की भी समीक्षा की।

जंगल में दो भालुओं का हमला, 56 वर्षीय तिवारी गंभीर रूप से घायल

■ खेत जाने के दौरान अचानक दो भालुओं ने बोला हमला, सिर और हाथ में आई गंभीर चोटें

सूरजपुर। रामानुजनगर जिले के ग्राम साल्ही (आमगांव) निवासी 56 वर्षीय तिवारी सिंह पर जंगल में दो भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। घटना लगभग शाम 5 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, तिवारी सिंह खेत की ओर गए हुए थे, तभी जंगल में मौजूद दो भालुओं ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। अचानक हुए भालुओं के हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना ने



एक बार फिर जंगल से लगे ग्रामीण इलाकों में वन्यजीवों के हमले और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने तथा जंगल और खेतों की ओर जाने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

संक्षिप्त समाचार

हेगसेथ पर महाभियोग की कोशिश नाकाम: ट्रंप के सांसदों ने बचाई कुर्सी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को पद से हटाने की कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया। मंगलवार रात हुए मतदान में 211 सांसदों ने प्रस्ताव को समिति के पास भेजने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 204 सांसद इसके विरोध में थे। इस प्रक्रिया के चलते प्रस्ताव पर सदन में सीधे बहस और मतदान नहीं हो सका। रिपब्लिकन नेताओं और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कोशिश को नाकाम करने के लिए पर्दे के पीछे से काफी मशक्कत की। हालांकि, यह हेगसेथ के लिए स्थायी राहत नहीं है।

रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ आरोपों वाला प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री ने अमेरिकी संविधान और युद्ध शक्तियों से जुड़े कानून का उल्लंघन किया है। मैसी के मुताबिक, हेगसेथ ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना कई सैन्य अभियान चलाए। इनमें ईरान और यमन पर सैन्य हमले के साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए चलाया गया अभियान भी शामिल है। मैसी ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी नहीं होने पर सेना को 60 दिनों के भीतर सैन्य संघर्ष से हटना जरूरी है। मैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी हेगसेथ के खिलाफ अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को शुरू हुए 256 दिन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इसे मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत 60 दिनों के भीतर सेना को संघर्ष से वापस बुलाया जाना चाहिए था। मैसी ने आरोप लगाया कि हेगसेथ इस कानून को तोड़ रहे हैं।

दूसरी ओर, हेगसेथ का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से किए गए सभी सैन्य अभियान कानूनी थे और राष्ट्रपति को देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर के रूप में मिले अधिकारों के तहत चलाए गए। फिलहाल महाभियोग प्रस्ताव को रोकने में रिपब्लिकन सांसद सफल रहे हैं, लेकिन जनवरी में अमेरिकी संसद का समीकरण बदलने वाला है। मौजूदा कांग्रेस के आखिरी सत्र में रिपब्लिकन पार्टी के पास बेहद मामूली बहुमत है। मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। ऐसे में जनवरी में 120वीं कांग्रेस के गठन के बाद प्रतिनिधि सभा की कमान डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हकीम जेफ्रीज के नेतृत्व में आने की उम्मीद है। नई बहुमत वाली पार्टी हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कोशिश दोबारा शुरू कर सकती है। हेगसेथ ने महाभियोग की कोशिश को खारिज किया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके खिलाफ हुई महाभियोग की दो असफल कोशिशों का जिक्र किया। हेगसेथ ने कहा, 'हम यह तमाशा पहले भी देख चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक फोन कॉल को लेकर महाभियोग चलाया। उनके कार्यकाल के आखिरी सप्ताह में दूसरी बार ऐसा किया। दोनों बार वे असफल रहे। अब तीसरी बार वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार निशाने पर उनके मंत्रिमंडल का एक सदस्य है।' उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करने पर उन्हें गर्व है और यह कोशिश भी नाकाम होगी। ट्रंप ने भी हेगसेथ का समर्थन करते हुए ट्रुथ सोशल पर उन्हें 'ए प्लस प्लस प्लस' ग्रेड दिया। साथ ही प्रस्ताव लाने वाले थॉमस मैसी को नाराज, हारा हुआ और पूरी तरह असफल नेता बताया।

ट्रंप के समर्थन में इस्राइल, कहा- हमास का निरस्त्रीकरण अनिवार्य

यरुशलम, एजेंसी। इस्राइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए हमास के तत्काल निरस्त्रीकरण को अनिवार्य बताया है। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्री योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस्राइल ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों से हमास को तुरंत हथियार डालने की मांग करने का आग्रह किया। समूह का हथियार सौंपने से इन्कार पुनर्निर्माण में मुख्य बाधा बना हुआ है। इस्राइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर 'गाजा और शांति बोर्ड पर बयान' शीर्षक से एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें वाशिंगटन के साथ समन्वय और मानवीय राहत प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। बयान में कहा गया कि इस्राइल अमेरिका और शांति बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस्राइल डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्री योजना की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के तहत, पुनर्निर्माण शुरू होने से पहले हमास को निरस्त्र होना होगा और गाजा को विसैन्यीकृत करना होगा।

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला: चीनी सामानों पर टैरिफ छूट दो महीने के लिए बढ़ाई

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने चीनी सामानों की 178 श्रेणियों पर अतिरिक्त शुल्क से मिली छूट को 9 जनवरी, 2027 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापार प्रतिबद्धताओं को लेकर बातचीत जारी है।अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने मंगलवार (स्थानीय समय) को 'फेडरल रजिस्टर' में एक नोटिस जारी करके छूट की अवधि को दो महीने और बढ़ाने की घोषणा की। इससे 9 नवंबर के बाद ये छूट खत्म नहीं होंगी।

इस फैसले से अमेरिकी आयातकों को कुछ खास चीनी उत्पादों को बिना अतिरिक्त शुल्क चुकाए मंगाना जारी रखने की अनुमति मिल गई है। ये अतिरिक्त शुल्क 'ट्रेड एक्ट ऑफ 1974' की धारा 301 के तहत लगाए गए थे। यह विस्तार उन सामानों पर लागू होगा जो 10 नवंबर, 2026 से लेकर 9 जनवरी, 2027 को रात 11:59 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक अमेरिका में आएंगे। नोटिस में कहा गया है, 'चीन के साथ चल रही बातचीत को देखते हुए, व्यापार प्रतिनिधि ने तय किया है कि अभी दी गई सभी 178 छूटों को 10 जनवरी, 2027 तक बढ़ाना उचित होगा।'

इन छूटों में 164 उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं, जिन्हें पहले के टैरिफ राहत उपायों से आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा, इसमें सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली 14 श्रेणियां भी शामिल हैं। ये छूट केवल उन्हीं उत्पादों पर लागू होती हैं जो विशिष्ट कस्टम वर्गीकरण और विवरणों की शर्तों को पूरा करते हैं। चीन से होने वाले अन्य आयात पर पहले की तरह ही टैरिफ लागू रहेंगे। यूएसटीआर (यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव) ने बताया कि यह विस्तार देने से पहले, पिछली समीक्षाओं के दौरान मिली सार्वजनिक



टिप्पणियों, सलाहकार समितियों की सिफारिशों और 'सेक्शन 301 कमेटी' (जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मिलकर बनी है) की सलाह पर विचार किया गया। एजेंसी ने भविष्य में और बदलावों की संभावना भी खुली रखी है।

नोटिस में कहा गया है, 'ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जरूरत के हिसाब से आगे और विस्तार देने या अन्य बदलाव करने पर विचार कर सकते हैं।' यह घोषणा 6 नवंबर को अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की, चीन के वाइस प्रीमियर हे लिफेंग के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के चार दिन बाद आई है। इस बातचीत के दौरान, ग्रीर ने बीजिंग से आग्रह किया कि वह पिछले व्यापार समझौतों के तहत किए गए वादों को पूरा करे। इनमें विशेष रूप से अमेरिकी कृषि निर्यात, 'रेयर अर्थ' तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े वादे शामिल हैं। ग्रीर ने इस बात पर जोर दिया कि चीन को इन वादों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रशासन ने कहा कि वह समझौतों के पालन पर नजर रखना जारी रखेगा। साथ ही, वह एक ऐसा संतुलित व्यापार संबंध बनाने की कोशिश करेगा जिससे अमेरिकी किसानों, निर्माताओं और श्रमिकों को फायदा हो। यह विस्तार, अन्य बातों के अलावा, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच बनी एक व्यापार समझ (ट्रेड अंडरस्टैंडिंग) पर आधारित है। उस समझौते के तहत, वाशिंगटन कुछ अतिरिक्त टैरिफ से छूट बनाए रखने पर सहमत हुआ था। वहीं, बीजिंग ने अमेरिकी सामानों पर अपनी छूट को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने का वादा किया था। इस समझौते में अमेरिकी कृषि उत्पादों की चीन द्वारा खरीद, 'रेयर अर्थ' तत्वों के निर्यात पर लगी पाबंदियां, और अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों को प्रभावित करने वाले व्यापार उपायों जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था।

शेख हसीना की वापसी की आहट से बांग्लादेश में हिंसा

बीएनपी का दफ्तर खाक, बसें भी फूंकीं; ड्राइवर जिंदा जला

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के स्वदेश लौटने की तैयारियों के बीच राजधानी ढाका और आसपास के कई जिलों में सोमवार देर रात हिंसा भड़क उठी। हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों और विरोधियों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुईं। देसी बम धमाकों, पुलिस की गाड़ियों पर हमलों और बसें फूंकने की कई घटनाओं के बीच खगड़ाछड़ी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक वार्ड कार्यालय को फूंक दिया गया। वहीं, फरीदपुर में एक बस को आग के हवाले करने की घटना में उसमें सो रहा ड्राइवर जिंदा जल गया।

पुलिस ने ताजा हिंसक घटनाओं के लिए हसीना की पार्टी अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश पुलिस के अनुसार, अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार तड़के शरियतपुर जिले में पद्मा ब्रिज के दक्षिणी टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। उन्होंने देसी बम फोड़े और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिससे कुछ समय के लिए पुल पर यातायात बाधित रहा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी जिले नेत्रकोणा के मोहनगंज स्टेशन पर खड़ी अंतरप्रांतीय ट्रेन हाओर एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई। हालांकि, रेलवे और दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे ट्रेन



सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं। अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार सुबह हसीना के गृहनगर तुंगीपारा में पुलिस और प्रतिबंधित छात्र संगठन छात्र लीग व अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान पुलिस की एक गाड़ी को भी फूंक दिया गया। ढाका-खुलना हाईवे पर पेड़ काटकर रास्ता बंद करने की कोशिश की गई। पुलिस ने हटाकर यातायात बहाल कराया। अनवारा में ग्रामीण बैंक की एक शाखा पर बम फेंकने से कागज़ात जल गए, जबकि रंगामाटी में अदालत और तीन शिक्षण संस्थानों के मुख्य दरवाजों पर रात के अंधेरे में ताले जड़ दिए गए। हिंसा ऐसे समय भड़की है जब सरकार ने कहा है कि वह शेखहसीना की तरफ से नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने संबंधी खबरों की जांच कर रही है।

पूर्व पीएम का प्रत्यर्पण चाहता है बांग्लादेश

हसीना (79) अगस्त 2024 में छात्र नीत तख्तापलट के बाद से भारत में रह रही हैं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जुलाई-अगस्त 2024 के प्रदर्शनों के दौरान नरसंहार के मामले में हसीना को दोषी ठहराया था। उनकी अनुपस्थिति में चले इस मुकदमे में अदालत ने उन्हें एक मामले में मृत्युदंड और दूसरे में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस साल फरवरी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के सत्ता में आने और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बांग्लादेश भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर कायम है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने स्पष्ट किया है कि हसीना के पास मौत की सजा के फैसले के खिलाफ कानूनी रूप से कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। उन्हें इस सजा का सामना करना ही होगा। न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को छात्र आंदोलन के दौरान हिंसक प्रदर्शनों और मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा उनकी अनुपस्थिति में सुनाई थी।

तंबाकू कंपनी के खेल का किया पर्दाफाश: मिलीं जान से मारने की धमकियां; अब दूसरों को जेफ्री सिखा रहे सच की लड़ाई

पेरिस, एजेंसी। वो 1990 का दशक था, तंबाकू कंपनियों का सिक्का पूरी दुनिया में चलता था और सिगरेट के धुएं में लोगों की सेहत उड़ रही थी। उस वक्त एक ऐसा तूफान उठा जिसने इस अरबों-खरबों डॉलर के उद्योग की चूलें हिलाकर रख दीं। यह वो कहानी है जिसने जेफ्री विगैंड को इतिहास का सबसे साहसी व्हिसलब्लोअर बना दिया। विगैंड तंबाकू दिग्गज ब्राउन एंड विलियमसन में टॉप साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबूतों के साथ पर्दाफाश किया कि तंबाकू कंपनियां सिगरेट में जानबूझकर रसायनों की हेरफेर करती हैं ताकि लोगों को इसकी लत लग जाए। इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलीं, उनकी शादी टूट गई, करियर खत्म हो गया और वह हाईस्कूल में मामूली टीचर बन गए। डॉ. विगैंड 83 वर्ष के हो चुके हैं और गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से जूझ रहे हैं। लेकिन सच सामने लाने का उनका जज्बा आज भी उसी तरह बरकरार है। वह उन तमाम लोगों के लिए गाइड और संरक्षक बन चुके हैं, जो सत्ता या कॉर्पोरेट धांधली के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जोखिम उठाने की सोच रहे हैं। डॉ. विगैंड बताते हैं, मैं अब बेजान-सा चलता हूं लेकिन जब भी किसी बेबस इंसान का फोन आता है तो उसकी बात पूरे ध्यान से सुनता हूं। इंटरनेट पर उनका फोन नंबर सार्वजनिक है और हर रोजा उनके पास जापान के रिसर्च लैब्स से लेकर अमेरिकी रक्षा एजेंसियों तक के कर्मचारियों के फोन आते हैं। विगैंड के छोटे भाई जेम्स कहते हैं, 83 वर्ष की उम्र में जहां ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी बिताते हैं, वहीं उनके भाई का फोन दिन-रात बजता रहता है। वह एक जिद्दी योद्धा है, उसके अंदर सच के लिए लड़ने का अद्भुत जज्बा है। जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति अपनी नौकरी और जान जोखिम में डालकर गलत के खिलाफ बोलना चाहता है तो सबसे पहले जेफ्री विगांड को याद करता है। विगैंड उन्हें समझाते हैं कि इस खतरनाक रास्ते पर कैसे चलना है, सबूत कैसे सुरक्षित रखने हैं और खुद को मानसिक रूप से कैसे मजबूत रखना है। डॉ. विगैंड से संपर्क करने वाले 50% से भी कम लोग अंततः अपनी कंपनी या सरकार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर खड़े हो पाते हैं।

एसयूवी कार की टक्कर से लॉस एंजिलिस में तीन की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच



वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजिलिस में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां नॉर्थ हॉलीवुड में मेट्रो स्टेशन के पास फुटपाथ पर चल रहे लोगों को एक तेज रफ्तार सफेद एसयूवी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। लॉस एंजिलिस अग्निशमन विभाग (एलएएफडी) ने इसकी जानकारी दी।

लॉस एंजिलिस पुलिस विभाग (एलएपीडी) के मुताबिक, व्यस्त चौराहे पर शाम करीब छह बजे से ठीक पहले एक सफेद एसयूवी ने कम से कम पांच लोगों को टक्कर मारी। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम तीन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें वाहन का चालक भी शामिल है। फिलहाल अभी तक हादसे की वजह सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है। मंगलवार रात आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलएपीडी के कैप्टन वार्नर कैस्टिलो ने कहा, 'हमें नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया था या दुर्घटनावश हुआ।' कैस्टिलो के मुताबिक, एसयूवी चालक की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। उसकी उम्र 60 साल के आसपास है। अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए उसकी चिकित्सकीय जांच शुरू की है कि कहीं वह नशे के प्रभाव में तो वाहन नहीं चला रहा था। लॉस एंजिलिस की मेयर करेन बास ने बताया कि हादसे के शिकार लोगों में सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेता और राहगीर शामिल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया। मेयर ने लिखा, 'इस हादसे से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के लिए मेरा दिल दुखी है।' वहीं, एलएपीडी के प्रमुख जिम मैकडॉनेल ने बताया कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच लंबी चलेगी, लेकिन इसे बेहद सावधानी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा।

ब्रिटेन में एयरबेस उड़ाने की थी साजिश, ईरान समर्थित नेटवर्क के तीन लोगों पर शिकंजा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अभियोजकों ने यूरोप में हमलों और अमेरिका में हिंसक वारदातों की साजिश रचने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े मामले दर्ज किए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, यह अभियान ईरान समर्थित था। इसमें ब्रिटेन के एक सैन्य एयरबेस पर हमले की नाकाम कोशिश भी शामिल थी, जहां उस समय अमेरिकी सैन्यकर्मी और विमान मौजूद थे।

अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में आठ आरोपों वाली एक संशोधित अभियोग-पत्र (सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट) दाखिल की गई है। इसमें मोहम्मद बाकिर साद दाऊद अल-सादी (ईरानी-इराकी दोहरी नागरिकता), ईरानी नागरिक मोहसेन मोहाजेरी और इराकी नागरिक मोहम्मद अली अल-हसानी को आरोपी बनाया गया है।

क्या है आरोप

इन लोगों पर ईरान के 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (आईआरजीसी) और 'कताइब हिजबुल्लाह' को समर्थन देने का आरोप है। अमेरिका ने इन दोनों संगठनों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। अभियोजकों के अनुसार, यह नेटवर्क लगभग 20 हमलों और हमलों की कोशिशों से जुड़ा है।

ब्रिटिश एयरबेस 'रॉयल फेयरफोर्ड' को बनाया था निशाना: अभियोजकों के मुताबिक, इस कथित साजिश का सबसे हालिया निशाना ब्रिटेन का 'रॉयल फेयरफोर्ड' एयरबेस था। सितंबर में हमले की कोशिश के समय इस एयरबेस पर अमेरिकी विमान और सैन्यकर्मी तैनात थे। आरोपपत्र के अनुसार, अल-हसानी ने विदेश में रहते हुए ब्रिटेन में



मौजूद अपने सहयोगियों की मदद से हमले की योजना तैयार की थी। उस समय मोहाजेरी भी ईरान में था, जबकि अल-सादी पहले से ही आतंकवाद से जुड़े एक अन्य मामले में न्यूयॉर्क की संघीय हिरासत में बंद था। अभियोजकों का दावा है कि जेल में होने के बावजूद अल-सादी ने इराक में अपने रिश्तेदारों से फोन पर बातचीत के जरिए सहयोगियों तक गुप्त संदेश पहुंचाए।

अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक, हमले की तैयारियां अगस्त में शुरू हुई थीं। आरोपियों के सहयोगियों ने एयरबेस की निगरानी और रेकी की। इसके अलावा वैन और ईंधन के ड्रम जुटाए गए। रासायनिक ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल पर जानकारी जुटाई गई और छर्रे के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले धातु के सामान भी हासिल किए गए। अभियोजकों ने बताया कि वैन पर ऐसे निशान लगाए गए थे, जिससे वे ईंधन की आपूर्ति करने वाली या स्विमिंग पूल से जुड़ी कंपनियों की गाड़ियां दिखाई दें। आरोपपत्र में यूरोप के यहूदी समुदायों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कथित श्रृंखला का भी जिक्र है। अभियोजकों का कहना है कि आरोपी 'हरकत अशाब अल-यामिन अल-इस्लामिया' नाम के एक समूह के जरिए काम कर रहे थे। इसे ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों का मुखौटा संगठन बताया गया है।

इस समूह ने यूरोप में 18 हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इनमें से सात हमले ब्रिटेन में हुए थे। इन घटनाओं में आगजनी, विस्फोटक हमले और लंदन में दो यहूदी लोगों पर चाकू से किया गया जानलेवा हमला शामिल था। इस हमले में एक व्यक्ति की जान बाल-बाल बची थी। वह ब्रिटिश और अमेरिकी, दोनों देशों की नागरिकता रखता था।

आतंकवादी संगठनों को मदद और हमले की साजिश समेत कई आरोप

अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से दाखिल आरोपपत्र में कई गंभीर आरोप शामिल हैं। इनमें अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित समूहों को भौतिक सहायता मुहैया कराने की साजिश, आतंकवाद के वित्तपोषण और सार्वजनिक स्थान पर बम विस्फोट करने की साजिश शामिल हैं। मामले की जांच के आधार पर अभियोजकों ने तीनों आरोपियों को कथित ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा बताया है। हालांकि, ये सभी आरोप हैं और अदालत में अभी इनकी पुष्टि होनी बाकी है।

चक शूमर ने ट्रंप को घेरा, कहा- जेन्सेन हुआंग पर कार्रवाई के बजाय लिया 234 करोड़ रुपये का चंदा

वॉशिंगटन, एजेंसी। एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग के कथित तौर पर चीनी जासूस से संबंधों को लेकर अमेरिका में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप को एक साल से अधिक समय पहले हुआंग के एक कथित चीनी जासूस के साथ संबंधों की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। शूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप को एनवीडिया के सीईओ और कथित चीनी जासूस के संबंधों के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।

शूमर ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने इसके बजाय हुआंग को बीजिंग की यात्रा पर साथ ले गए, चीन को अमेरिकी एआई चिप्स तक पहुंच देने की उनकी सलाह मानी और एनवीडिया से 25 मिलियन डॉलर



का चंदा स्वीकार किया। उन्होंने व्हाइट हाउस से तत्काल जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने में ट्रंप प्रशासन की कथित नाकामी पर तुरंत जवाब मिलना चाहिए। शूमर का यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जेन्सेन हुआंग का सार्वजनिक रूप से बचाव किए जाने के कुछ समय बाद आया है। ट्रंप ने हुआंग को शानदार और उच्च गुणवत्ता वाला व्यक्ति बताया था। उन्होंने एनवीडिया की ओर से विकसित ब्लैकवेल चिप की भी तारीफ की थी। हालांकि, ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इस पूरे विवाद से हुआंग और उनका परिवार काफी परेशानी झेल रहा है।

इस बीच एनवीडिया के बोर्ड ने मामले की स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक, बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पूर्व कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी जून एच. किम और उनकी कानूनी फर्म वाचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी ने कहा कि यह विस्तृत और स्वतंत्र जांच होगी। बोर्ड ने इससे पहले रविवार को भी जांच की घोषणा की थी।

एआई चिप निर्यात नीति पर भी उठे सवाल

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने भी ट्रंप प्रशासन की निर्यात नीति पर सवाल उठाए हैं। रोड आइलैंड के गैब अमो, न्यूयॉर्क के ग्रेगरी डब्ल्यू. मीक्स और कैलिफोर्निया की सिडनी कमलागर-डोव ने वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक से उन्नत एआई कंप्यूटर चिप्स के निर्यात की अनुमति से जुड़े सवालों का जवाब मांगा है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सांसदों ने कहा कि वाणिज्य विभाग ने चीन से जुड़े संस्थानों, सैन्य ठेकेदारों और प्रतिबंधित कंपनियों को उन्नत एआई हार्डवेयर भेजने की मंजूरी दी थी। सांसदों ने अपने पत्र में लिखा कि अमेरिका की एआई क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता की रक्षा करने का दावा करते हुए उसकी सबसे उन्नत तकनीक किसी रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी तक पहुंचने देना उचित नहीं है।

फ्रिज नहीं संभलते, देश की समस्याएं क्या संभालोगे': ईरान का फ्रांस पर तंज; होर्मुज में अमेरिका को भी ललकारा

तेहरान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका पर होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना के कमांडर ने कहा कि अमेरिकी सेना खुद इस रणनीतिक समुद्री रास्ते के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रही, लेकिन इसे खुला बताकर तेल टैंकरों को खतरे में भेज रही है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, कमांडर ने आरोप लगाया कि अमेरिका बेबस तेल टैंकरों को 'आग की दीवार' में धकेल रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बना हुआ है। अमेरिका के सामने ईरान ने रखीं सात शर्तें, ट्रंप ने क्या कहा इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने के लिए सात शर्तें रखी थीं। मानकर पश्चिम एशिया में नए समीकरण को स्वीकार करना चाहिए। इन शर्तों में सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म करना, होर्मुज के आसपास अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, समुद्री रास्ते को फिर खोलना, आर्थिक प्रतिबंध हटाना, विदेशों में जमा ईरान की संपत्तियां लौटाना और ईरान के आंतरिक मामलों में दखल बंद करना शामिल है।



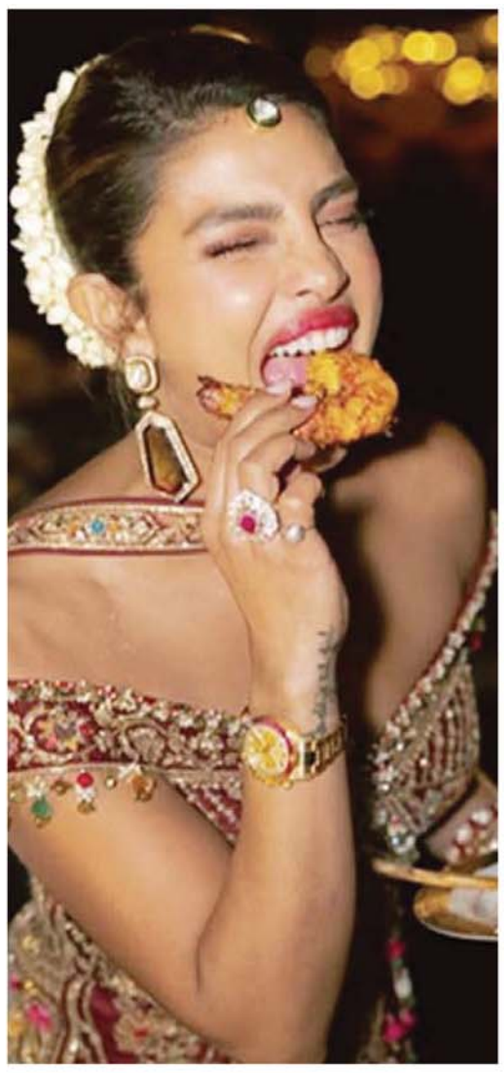
बिग बॉस से लॉकअप तक

पायल रोहतगी की जिंदगी से जुड़े ये दिलचस्प किस्से

बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी ने फिल्मों से लेकर रियलिटी शोज तक अपनी अलग पहचान बनाई है। कभी बड़े पर्दे पर अपने अभिनय से चर्चा बटोरने वाली पायल अपनी बेबाक बातों और रियलिटी शोज में अपने अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया और 'बिग बॉस' से लेकर 'लॉकअप' तक कई चर्चित शोज का हिस्सा बनीं। पायल रोहतगी का जन्म 9 नवंबर 1980 को हैदराबाद में हुआ था। वह पढ़ाई में काफी अच्छी थीं और उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह गुजरात बोर्ड की टॉपर भी रह चुकी हैं। हालांकि, पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका रुझान फिल्मों और एक्टिंग की तरफ बढ़ गया। साल 2000 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई विज्ञापनों में नजर आईं। धीरे-धीरे उन्हें फिल्मों में काम करने के मौके मिलने लगे। पायल ने साल 2002 में फिल्म 'ये क्या हो रहा है' से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वह 'तुमसे मिलकर', 'प्लान', 'पुलिस फोर्स: एन इनसाइड स्टोरी', 'रक्त', 'तौबा तौबा', 'लैला-ए मिस्ट्री' और 'चेतना: द एक्साइटमेंट' जैसी फिल्मों में नजर आईं। साल 2006 में आई फिल्म '36 चाइना टाउन' में उन्होंने ग्रेसी का किरदार निभाया। इसी साल वह फिल्म 'कॉरपोरेट' में भी नजर आईं। इसके बाद 2007 में आई 'ढोल' और 'हे बेबी' में भी उन्होंने काम किया। वहीं, 'अपना सपना मनी मनी', 'उगली और पगली', 'दिल कबड्डी' और 'वैलेंटाइंस नाइट' भी उनकी फिल्मों में शामिल हैं।

फिल्मों के अलावा पायल ने छोटे पर्दे पर भी खूब काम किया। साल 2008 में वह रियलिटी शो 'बिग बॉस 2' में नजर आईं। इस शो में उनके बेबाक अंदाज ने खूब चर्चा बटोरी। इसके बाद वह 'राज पिछले जन्म का', 'जोर का झटका', 'सर्वाइवर इंडिया', 'नच बलिए 7' और 'बिग बॉस 7' जैसे शोज का हिस्सा बनीं। पायल ने टीवी के कई धारावाहिकों में भी काम किया। इनमें 'हमने ली है शपथ', 'हमसफर्स', 'एजेंट राघव' और 'सूर्यपुत्र कर्ण' जैसे शोज शामिल हैं। 'सूर्यपुत्र कर्ण' में उन्होंने अंबा और शिखंडिनी जैसे किरदार निभाए थे।

साल 2022 में पायल रोहतगी एक बार फिर रियलिटी शो को लेकर चर्चा में आईं। उन्होंने कंगना रनौत के शो 'लॉकअप' में हिस्सा लिया था।



दीपावली सेलिब्रेशन में नॉनवेज खाती नजर आईं प्रियंका चोपड़ा

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनस को लॉस एंजिल्स में दीपावली सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने लॉस एंजिल्स में अपने परिवार संग दीपावली सेलिब्रेशन की पार्टी रखी थी और पारंपरिक लिबास में तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिनमें वाइब, डेकोर और खाना शामिल था। उन्होंने अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ लॉस एंजेलिस स्थित अपने घर पर दीपावली मनाई थी और पारंपरिक लिबास में तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। शेयर की गई तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा के हाथ में फ्राइड प्राउन (झींगा) जैसा नॉन-वेज फूड दिखाई दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दिवाली के दिन मांसाहार को लेकर उनकी आलोचना की।

कई यूजर्स ने उनके पुराने बयानों को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने दिवाली पर पटाखे न चलाने की अपील की थी। कुछ लोगों ने तंज कसा कि अस्थमा का नियम सिर्फ दिवाली पर ही क्यों याद आता है। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'दीपावली में नॉनवेज।'

एक और यूजर ने लिखा, 'दीपावली पर कोई नॉनवेज कैसे खा सकता है और कैंडल क्यों, दीये क्यों नहीं।' प्रियंका अक्सर विदेश में रहते हुए भी अपनी भारतीय परंपराओं को जीवित रखने की बात कही है। उन्होंने निक और मालती के साथ अपनी फैमिली लाइफ में भारतीय रीति-रिवाजों और त्योहारों को हमेशा जगह दी है।



राम चरण, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन समेत कई सितारों ने दीपावली की शुभकामनाएं दीं

दीपावली के शुभ अवसर पर, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की कई जानी-मानी हस्तियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए शुभकामनाएं दीं। 'आरआरआर' फेम अभिनेता राम चरण ने सोशल मीडिया प्?लेटफॉर्म एक?स पर लिखा, 'आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके और आपके अपनों के जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए। आपकी दीपावली सुरक्षित और शानदार हो।' जूनियर एनटीआर ने बहुत ही सरल और प्यारे शब्दों में दीपावली की बधाई देते हुए लिखा, 'आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।' अभिनेता धनुष ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, 'सभी को दिल से दीपावली की शुभकामनाएं। हर दिल खुशियों से भर जाए और हर घर में प्यार का प्रकाश फैले।' मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने एक दीपक की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'हैप्पी दीपावली।' अभिनेता अल्लू अर्जुन ने देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर साझा की और लिखा, 'आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।' कार्थी ने लिखा, 'प्यारे दोस्तों, आपकी दुनिया हमेशा खुशियों, सफलता और ढेर सारे आशीर्वादों से जगमगाती रहे!' विष्णु मांचू ने अपने परिवार की एक खूबसूरत तस्वीर साझा करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'वीएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि बनी रहे। आपके साथ आपके सबसे प्रिय लोग रहें।'

करीना कपूर के दिवाली लुक में दिखी शाही विरासत की झलक

पहनी 200 साल पुरानी कलगी

अभिनेत्री करीना कपूर खान की फेस्टिव लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब चर्चा बटोर रही हैं। एक्ट्रेस न मुंबई स्थित घर की बालकनी में पोज दिए, जिसे फेस्टिव लाइट्स और फूलों की सजावट से सजाया गया था। उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने की झलक दिखाई। अभिनेत्री करीना कपूर खान ने रिया कपूर द्वारा स्टाइल किया गया नवाबी लुक दिवाली के उत्सव के लिए अपनाया था। रिया ने बताया कि इसमें भोपाल के शाही परिवार की बेशकीमती विरासत वाली ज्वेलरी भी शामिल थी। करीना के फेस्टिव लुक की तस्वीरें शेयर करते हुए रिया ने उन्हें असली मूवी स्टार बताया और उनके आउटफिट और ज्वेलरी के निजी महत्व को भी बताया। करीना ने डिजाइनर पुनीत बलाना द्वारा तैयार किया गया बेज रंग का कफ्तान पहना था। इस पर चांदी के तारों की बारीक कढ़ाई की गई थी। इसके साथ उन्होंने मैचिंग बेज रंग की पगड़ी (टर्बन) पहनी थी, जो उन्हें एक पारंपरिक नवाबी लुक दे रही थी। इस लुक का सबसे मुख्य आकर्षण उनकी पगड़ी पर लगी लगभग 200 साल पुरानी हीरे-जवाहरात जड़ी 'कलगी' थी। यह कलगी पटौदी और भोपाल के शाही परिवार की विरासत है, जिसे सैफ अली खान ने अपनी शादी में पहना था और उनसे पहले भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान भी इसे पहनते थे। रिया ने ज्वेलरी के पीछे के पारिवारिक जुड़ाव को भी समझाया। उन्होंने बताया कि ये टुकड़े करीना के अपने कलेक्शन के थे और उनके पति सैफ अली खान के परिवार से आए थे। सैफ की दादी साजिदा सुल्तान भोपाल के अंतिम शासक नवाब की बेटी थीं। करीना की तस्वीरें शेयर करते हुए रिया ने लिखा, 'असली मूवी स्टार, असली चांदी, असली विरासत और असली पर्सनल स्टाइल।





बच्चों को दीपावली के रीति-रिवाज सिखा रहीं इशिता दत्ता

बताया- 'चाहती हूं वे भी इन्हें आगे बढ़ाएं'

अभिनेत्री इशिता दत्ता ने दीपावली त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाया। घर पर मिठाइयां बनाना, लक्ष्मी पूजा करना, दीप जलाना और रंगोली बनाना उनके त्योहार का अहम हिस्सा है। वह अपने बच्चों को भी इन परंपराओं से जोड़ रही हैं, ताकि वे भी बड़े होकर इन्हें आगे बढ़ाएं। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में इशिता ने बताया कि उनके घर में दीपावली का जश्न बहुत सादगी से मनाया जाता है। इस दिन पूरा परिवार सुबह एक साथ उठता है और पूजा के लिए घर पर मिठाइयां बनाता है। इसके बाद घर में छोटी-सी लक्ष्मी पूजा होती है और बाहर दीप जलाए जाते हैं। अभिनेत्री ने कहा, ''हमारे घर में दीपावली बहुत सादगी से मनाई जाती है। सुबह उठते हैं और पूरा परिवार एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देता है। पूजा के लिए घर पर मिठाइयां बनाते हैं। घर में छोटी-सी लक्ष्मी पूजा होती है और बाहर दीपक जलाएं जाते हैं। दीपक जलाने की तैयारियां तो कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। दीपावली के दिन यही सब छोटी-छोटी चीजें होती हैं। शाम को कभी-कभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं। हर दीपावली पर होने वाली काली पूजा में भी शामिल होते हैं और इसी के साथ हमारा दिन खत्म होता है।''

इशिता का मानना है कि त्योहार परिवार को एक साथ लाने का सबसे अच्छा मौका होते हैं। उन्हें पुरानी परंपराओं को निभाना पसंद है और अब वह अपने बच्चों को भी इनके बारे में सिखा रही हैं।

उन्होंने कहा, ''मुझे परंपराएं बहुत पसंद हैं और मैं उन्हें निभाना भी पसंद करती हूं। अब मुझे अपने बच्चों को ये परंपराएं सिखाना अच्छा लगता है। उम्मीद है कि एक दिन वे भी इन्हें आगे बढ़ाएंगे। मुझे त्योहार इसलिए पसंद हैं, क्योंकि इनके बहाने पूरा परिवार एक साथ आता है।

दीपावली पर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने बेटे विहान की फोटो इंस्टाग्राम पर की शेयर

बॉलीवुड की सेलिब्रिटी कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने बेटे विहान का चेहरा फैन्स को दिखाया है। रविवार को कपल ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को अपने बेटे से मिलवाया। तस्वीर में विहान को खुशी-खुशी अपनी बाहें फैलाते हुए देखा जा सकता है, जबकि उसके माता-पिता उसे पीछे से पकड़े हुए हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हमारी अब तक की सबसे शानदार दीपावली। सभी को प्यार, रोशनी और खुशी की शुभकामनाएं। विक्की, कैटरीना और विहान।'

नवंबर 2025 में कपल के घर पहला बच्चा आया, जिसका नाम विहान कौशल रखा गया। कपल ने जनवरी 2026 में सोशल मीडिया पर बच्चे का नाम और पहली झलक शेयर करते हुए इस खबर को पब्लिकली कंफर्म किया।

एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी को काफी हद तक प्राइवेट रखा और उस दौरान अक्सर पब्लिक में आने से दूर रहीं। पेरेंट्स बनने के बाद से, दोनों एक्टर्स को काम और फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाते हुए चुनिंदा जगहों पर देखा गया है। कपल ने अपने बेटे का नाम कॉम्बैट फिल्म 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' में विक्की के कैरेक्टर पर रखा।

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के शानदार सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। शादी का जश्न तीन दिनों तक चला और इसमें हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी जैसे पारंपरिक फंक्शन शामिल थे। करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य सेलिब्रेशन में शामिल हुए, जबकि पूरे इवेंट में प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया। शादी की रस्मों के लिए कपल ने सब्यसाची मुखर्जी के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने थे। कैटरीना ने ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ लाल लहंगा पहना था, जबकि विक्की आइवरी शेरवानी में दिखे।



सेरेमनी के बाद, एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर शादी की ऑफिशियल तस्वीरें शेयर कीं, जो वायरल हुई थीं। उनकी शादी भारत की सबसे चर्चित सेलिब्रिटी शादियों में से एक बन गई, जिसे इसके रॉयल माहौल, खास मेहमानों की लिस्ट और शानदार ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन के लिए सराहा गया। इस बीच, विक्की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है। इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी हैं। यह फिल्म रणबीर और आलिया दोनों के साथ विक्की की दूसरी कोलैबोरेशन है। फिल्म जनवरी 2027 में थिएटर में रिलीज होने वाली है।

'ममूट्टी-ममूट्टी कहते-कहते अब उनके साथ काम कर रही हूं, शायद मैंने ही मैनिफेस्ट कर लिया!' - साई पल्लवी

ओमः चैप्टर 1 - उधिरमः द ब्लड वुड' के ग्रैंड ऑडियो लॉन्च का, जहां हजारों की तादाद में पहुंचे फैंस ने इस शाम को किसी बड़े फिल्मी जश्न में बदल दिया। धनुष, ममूट्टी, साई पल्लवी, श्रीलीला, निर्देशक राजकुमार पेरियासामी, निर्माता श्रद्धा अग्रवाल और म्यूजिक कंपोजर साई अभ्यंकर की मौजूदगी ने इस महफिल में चार चांद लगा दिए। फिल्म के इस खास जश्न में निर्माता श्रद्धा अग्रवाल ने कहा, 'आरटेक बैनर के तहत हमने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, उन सभी का चेन्नई से एक खास रिश्ता रहा है। लेकिन 'ओम' के साथ हम इस रिश्ते को और भी बड़े स्तर पर लेकर जा रहे हैं। यह निस्संदेह हमारी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। धनुष सर जैसे इंसान के साथ यह सफर बेहद खूबसूरत रहा है। वहीं राजकुमार सर की फिल्म के प्रति मेहनत, लगन और



समर्पण शानदार रहा है। 'ओम' को लेकर दर्शकों ने अब तक जो प्यार और उत्साह दिखाया है, वह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उम्मीद है कि 20 नवंबर को फिल्म सिनेमाघरों में पहुंचने के बाद यह प्यार और भी बढ़ेगा।' वहीं साई पल्लवी ने अपने खास अंदाज में मम्मूट्टी के साथ काम करने का अनुभव साझा करते हुए कहा, 'पिछली फिल्म में मैं मम्मूट्टी-मम्मूट्टी कहती रहती थी और अब मम्मूट्टी सर के साथ काम कर रही हूं। पता नहीं, मैंने ही इसे मैनिफेस्ट कर लिया था!'

मम्मूट्टी के साथ काम करने के अनुभव पर साई बोलीं, 'वह 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन मैंने सेट पर उनसे ज्यादा एनर्जेटिक एक्टर नहीं देखा। वह बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। कैमरा रोल होने से पहले ही वह ऐसे प्यारे-प्यारे एक्सप्रेशंस देते रहते थे। उनके साथ काम करना मेरे लिए बेहद खुशी की बात रही।'

निर्माता श्रद्धा अग्रवाल ने फिल्म और चेन्नई के साथ अपने खास जुड़ाव पर कहा, 'आरटेक बैनर के तहत हमने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, उन सभी का चेन्नई से एक खास रिश्ता रहा है। लेकिन 'ओम' के साथ हम इस रिश्ते को और भी बड़े स्तर पर लेकर जा रहे हैं। यह निस्संदेह हमारी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने 21वीं अंतर जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का किया भव्य शुभारंभ

60 टीमों के 700 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हिस्सा, सभी टीमों को 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा

रायगढ़। 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला एवं पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप-2026 का भव्य शुभारंभ उत्साह एवं खेलमय वातावरण में हुआ। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने किया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की 60 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 700 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

उद्घाटन समारोह में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने स्वेच्छानुदान से प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा का खिलाड़ियों, खेल संगठनों एवं उपस्थित खेलप्रेमियों ने स्वागत किया। यह पहल प्रदेश में वॉलीबॉल खेल को प्रोत्साहित करने तथा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय कदम है।

समारोह में छत्तीसगढ़ स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री महेश गागड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मोहम्मद अकरम खान, सचिव श्री हेम प्रकाश नायक, संयुक्त सचिव श्री नितिन पाण्डेय सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी, खेलप्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने



विभिन्न जिलों से पहुंची टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। *रायपुर कार्पोरेशन वॉलीबॉल संघ के सदस्य श्री पंकज नायक ने जानकारी देते हुए बताया* कि इस प्रतियोगिता में रायपुर कार्पोरेशन की पुरुष एवं महिला दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने शुरुआती मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दोनों टीमों की इस उपलब्धि से संघ के पदाधिकारियों एवं खेलप्रेमियों में हर्ष का वातावरण है। श्री नायक ने विजयी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि रायपुर कार्पोरेशन की दोनों टीमें आगामी मुकाबलों में भी इसी उत्साह, अनुशासन एवं खेल भावना के साथ प्रदर्शन कर प्रतियोगिता में बेहतर स्थान प्राप्त करेंगी।

अन्य बैंकों में पेंशन खाता रखने वाले पेंशनरों को भी SBI में कराना होगा आधार लिंक

आधार लिंक नहीं होने पर पेंशन भुगतान में आ सकती है बाधा : वीरेन्द्र नामदेव

रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रदेश के समस्त पेंशनरों से अपने पेंशन खाते में आधार नंबर लिंक कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से उन पेंशनरों को सतर्क किया है, जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अलावा किसी अन्य बैंक में संचालित है। ऐसे पेंशनरों को भी अपने नजदीकी SBI शाखा में जाकर आधार लिंकिंग की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

श्री नामदेव ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों के संधारण एवं भुगतान संबंधी प्रक्रिया भारतीय स्टेट बैंक के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल (CPPC), रायपुर के माध्यम से की जा रही है। इसलिए अन्य बैंकों में पेंशन खाता होने के बावजूद आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में भविष्य में पेंशन भुगतान संबंधी तकनीकी अथवा प्रशासनिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अतः पेंशनर समय रहते यह औपचारिकता पूरी कर लें।

महासंघ के प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी ने पेंशनरों को आधार लिंक कराने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए पेंशनर अपने नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा अथवा SBI के CPPC रायपुर से संपर्क करें। अपने साथ पेंशन खाता नंबर एवं आधार कार्ड लेकर जाएं तथा बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें। आधार लिंकिंग के बाद बैंक से इसकी पुष्टि एवं पावती भी अवश्य प्राप्त करें।

महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे.पी. मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी एवं प्रवीण कुमार त्रिवेदी तथा संगठन मंत्री टी.पी. सिंह ने प्रदेश के सभी पेंशनर संगठनों, जिला एवं तहसील इकाइयों के पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इस महत्वपूर्ण सूचना को अपने-अपने क्षेत्रों के पेंशनरों तक पहुंचाएं, ताकि आधार लिंकिंग की प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण किसी भी पेंशनर को भविष्य में पेंशन भुगतान संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े।

लोक भवन में दीपावली मिलन समारोह आयोजित

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कर्मचारियों को दीपावली उपहार भेंट किए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत, सत्यम योग संस्थान के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया सम्मानित







रायपुर जनता के गोठ । लोक भवन में आज राज्यपाल श्री रमेन डेका की उपस्थिति में दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह में लोक भवन के अधिकारियों-कर्मचारियों और उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर लोक भवन परिवार के सदस्यों और उनके बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गीत-संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समारोह में उत्साह और उमंग का वातावरण बना दिया। समारोह के दौरान लोक भवन के कर्मचारियों और उनके परिजनों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने भी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। राज्यपाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने लोक भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दीपावली के उपहार भी भेंट किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने सत्यम योग संस्थान के सदस्यों को भी सम्मानित किया। योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने और उसके माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देने के लिए उन्होंने संस्थान के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग और भाईचारे का संदेश देता है। ऐसे आयोजन सभी को एक-दूसरे के साथ जुड़ने और पारिवारिक आत्मीयता के साथ त्योहार मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने समारोह में उत्साहपूर्वक भागीदारी के लिए लोक भवन परिवार के सभी सदस्यों की सराहना की। समारोह में राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे सहित लोक भवन के अधिकारी-कर्मचारी एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

बच्चों संग दीपावली मिलन बड़ी धूमधाम से मनाया गया : चडडा



रायपुर :- छत्तीसगढ़ टाइगर्स सोशल वर्कर्स एवं टैलेंट रिसर्च सेन्टर के तत्वधान में विगत 18 वर्षों से मना रहे दीपावली मिलन समारोह इस वर्ष भी

380 बच्चों एवं 50 बुजुर्ग माता तुल्य माताएं एवं 30 पिता तुल्य बुजुर्गों के साथ उन्हें नए कपड़े, पटाखे एवं मिठाई देकर बडे धूमधाम से मनाया गया।

इस कार्यक्रम को हमारे संरक्षक - मार्गदर्शक सम्मानीय सुरेश कंकारिया जी एवं स्वर्गीय जनाब इस्माइल मोहम्मद जी के मार्गदर्शन सहयोग से यह दीपावली मिलन समारोह झुग्गी झोपड़ी एवं फुटपाथ पर रह रहे गरीब परिवारों के बच्चे एवं माता - पिता तुल्य बुजुर्गों के साथ बड़े धूमधाम से दिलप्रीत नगर में मनाया गया।

इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ टाइगर्स सोशल वर्कर्स के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह चडडा , टैलेंट रिसर्च सेंटर की अध्यक्ष कोरीना मारिया

कुलदीप सिंह रंधावा, मेवा सिंह रामा अचल निर्मलकर, बदन निर्मलकर , राकेश धीवर,

छोटू नेताम, हेमलाल साहू बहन बलजीत कौर, सकुनतला देवी, भारती यादव , भुक्की धीवर

सहित अनेक बच्चे, भाई बहनों ने हिस्सा लेकर आपस में मिठाई खिलाकर दीपावली की इस पावन बेला में खुशियां बांटी और एक दूसरे के उज्ज्वल भविष्य की कामना की,

जनजातीय समाज भारत की आत्मा, 2047 के विकसित भारत का बनेगा मजबूत आधार: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयंती पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सीएम ने की महती पत्रकार वार्ता

विपक्ष पर साधा निशाना, बोले– 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त हुए जनजातीय जिलों में अब विकास की रफ्तार

किसानों को बड़ी सौगात: धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये की गई



जनता के गोठ

रायपुर (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जनजातीय समाज कोई वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र के साथ यह समाज वर्ष 2047 के विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार बन रहा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे 'जनजातीय गौरव सप्ताह' (11 से 18 नवंबर 2026) के तहत आयोजित महती पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

1857 से एक सदी पहले शुरू हुआ जनजातीय संग्राम, 2047 के लिए 8-सूत्रीय विज़न- भगवान बिरसा मुण्डा को नमन करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उलिहातू में जन्मे बिरसा मुण्डा ने महज 25 वर्ष की आयु में 'उलगुलान' और 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' का नारा देकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, जिसके फलस्वरूप 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। उन्होंने कहा कि 1857 से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, शहीद वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गाइदिन्ल्यू और मानगढ़ धाम के गोविंद गुरु जैसे नायकों ने स्वाधीनता संग्राम का बिगुल फूंक दिया था, जिन्हें दशकों तक इतिहास के पन्नों से गायब रखा गया।

मुख्यमंत्री ने 'विकसित भारत 2047' में जनजातीय भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आठ प्रमुख स्तंभों का उल्लेख कियाः- - बुनियादी सुविधाएं व शिक्षाः धरती आबा अभियान से 63 हजार गांवों में सड़क, बिजली, जल व आवास जैसी 25 सुविधाएं तथा जनजातीय बहुल ब्लॉकों में 728 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना।

- स्वास्थ्य व आजीविकाः 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाने का लक्ष्य, आयुष्मान योजना से 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 3,958 वन धन केंद्रों का सशक्तिकरण और 'लखपति दीदी' अभियान में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी।

- भाषा व नेतृत्व संरक्षणः 'आदि वाणी' एआई मंच से संथाली, भीली, मुंडारी व गोंडी भाषाओं का संरक्षण तथा 'आदि कर्मयोगी' अभियान से गांव-गांव में 20 लाख परिवर्तन के अगुआ तैयार करना।

बजट में 231त्न की ऐतिहासिक वृद्धि, विपक्ष के 12 भ्रमों का किया पर्दाफाश- मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटल जी की सरकार ने अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया और मोदी सरकार ने इसका बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से 231 प्रतिशत बढ़ाकर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये कर दिया है। देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय मुख्यमंत्रियों तक भाजपा ने समाज को शीर्ष नेतृत्व दिया है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम साय ने 12 बिंदुओं पर सच्चाई रखी और कहा कि 55 साल सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने जनजातीय नायकों की उपेक्षा की, पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति का विरोध किया और संविधान, आरक्षण व समान नागरिक संहिता (छष्ट) को लेकर झूठ फैलाया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना जैसे क्षेत्रों में घुसपैठ पर विपक्ष वोट बैंक के कारण चुप है, जबकि उसके शासन में पनपे नक्सलवाद को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 को जड़ से समाप्त कर जनजातीय जिलों को पूर्णतः नक्सल मुक्त बना दिया गया है।

किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं: फसल विविधीकरण पर अब ?15,000 प्रति एकड़- पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की भी जानकारी दीः - कृषक उन्नति योजनाः खरीफ 2023 से 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों के खाते में सीधे डीबीटी से ?35,904.90 करोड़ का भुगतान किया गया। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए खरीफ 2026 में धान के स्थान पर अन्य फसल, सब्जी या फल लगाने वाले पंजीकृत किसानों को प्रोत्साहन राशि ?11,000 से बढ़ाकर ?15,000 प्रति एकड़ की गई है।

- खाद की कालाबाजारी पर सख्तीः 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक 6,398 निरीक्षणों में अनियमितता पाए जाने पर 18 एफआईआर दर्ज की गई, 89 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पेश किए गए, 43 लाइसेंस निरस्त, 131 निलंबित, 148 मामलों में खाद जब्ती और 363 विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई की गई।

- दलहन-तिलहन की एमएसपी खरीदीः पीएम-आशा अभियान के तहत 2025-26 में 29 जिलों के 273 केंद्रों पर 3,72,039 क्विंटल अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर व सरसों की खरीदी कर किसानों को ?219.08 करोड़ का भुगतान किया गया। मक्का और गेहूं खरीदी पर भी शासन स्तर से जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा।

14 को दीपोत्सव और 15 नवंबर को प्रदेशभर में पुष्पांजलि- मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देश के 239 जनजातीय जिलों व 568 आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके तहत 14 नवंबर को स्मारकों की सफाई व दीपोत्सव, 15 नवंबर को प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि तथा 16 से 18 नवंबर तक 'युवा संवाद' और छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुण्डा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आह्वान किया। पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री रामविचार नेताम तथा छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम उपस्थित रहे।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक,संपादक–शुभम वर्मा द्वारा मकान नंबर 411, देवनगर, आदिवासी छात्रावास के सामने, शिव शंकर होटल के पीछे महादेव घाट रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित एवं छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स अनंत विहार कालोनी,दलदल सिवनी मार्ग –मोवा रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित। (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) फोनः–9300870270, 9425520408 jantakegoth@gmail.com